https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

भारत-जापान के बीच 75 अरब डॉलर की मुद्रा अदला-बदली पर समझौता

वर्ष-13, अंक-22 16-30 नवम्बर, 2018 (पाक्षिक) ₹20

एक भारत श्रेष्ठ भारत

राष्ट्रवाद से एकता का भूगोल रचने वाले पटेल

भारत में व्यापार करना हुआ सुगम

हिंदू परंपराओं को बचाने के लिए केरल में आक्रोश

कन्नूर (केरल) रैली में जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और केरल प्रदेश भाजपा नेतागण

कन्नूर (केरल) में पिनाराई गांव में भाजपा कार्यकर्ता श्री रमिथ (जिनकी कम्युनिस्टों ने हत्या कर दी) को श्रद्धांजलि देते और उनके परिवारजनों से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

हैदराबाद (तेलंगाना) में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा महाधिवेशन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भारत ने भविष्य के लिए प्रेरणा का आधार तैयार किया: नरेन्द्र मोदी

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को उनकी 143 वीं जयंती पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा...

वैचारिकी

सांस्कृतिक अधिष्ठान 14

श्रद्धांजलि

मदन लाल खुराना 16

लेख

राष्ट्रवाद से एकता का भूगोल रचने वाले पटेल 18

भारत में व्यापार करना हुआ सुगम 22

हिंदू परंपराओं को बचाने के लिए केरल में आक्रोश 24

साक्षात्कार

डॉ. अनिल जैन 28

अन्य

भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में 23 पायदानों की और... 12

'भारत एक मजबूत अर्थतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है' 17

भारत-जापान के बीच 75 अरब डॉलर की मुद्रा अदला-बदली पर... 20

'भाजपा का मानना है विकास ही सभी समस्याओं का समाधान' 30

लद्दाख के इतिहास से न्याय 32

मन की बात 33

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

व्यंग्य चित्र 04

08 जो कोई भारत को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जायेगा: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 28 अक्टूबर को परेड ग्राउंड,...

10 'हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान भारत को पुन: विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 अक्टूबर को कुन्नूर,...

11 सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को 59 मिनट में मिलेगा एक करोड़ तक का कर्ज

देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं...

13 आईएनएस अरिहन्त अपने पहले डेटरेंस पेट्रोल से लौटी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवंबर को भारत के स्ट्रेटजिक स्ट्राईक न्यूक्लियर सब्मरीन (SSBN)...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

छत्तीसगढ़ को काम करने वाली सरकार चाहिए। भाजपा की सरकार ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ का सिर्फ और सिर्फ विकास किया, अर्थव्यवस्था सुधारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल दिया।

@AmitShah

पूरी दुनिया को पता है कि नक्सलवाद इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस को नक्सलवाद में क्रांति दिखती है। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि बम के धमाकों और गोलियों से क्रांति नहीं होती, बल्कि साफ नीयत से गरीबों के घर में गैस, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने से क्रांति होती है।

@Ramlal

युवा पार्टी का भविष्य है, इसलिए एक शुभ संकल्प हम अपने जीवन के लिए लें, एक संकल्प पार्टी को बूथ पर मज़बूत बनाने के लिए और एक संकल्प देश के लिए लें। देश के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे व अच्छा करेंगे।

facebook

केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी जन-धन योजना के तहत देश के सभी परिवारों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है एवं हर परिवार का बैंक खाता खोला जा रहा है। मुझे बताते हुए अत्यन्त हर्ष है कि प्रदेश में अब तक 2.51 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं तथा 1.76 करोड़ खातों के रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। विशेषकर गरीब व वंचित वर्गों के बैंक खाते खुलने पर वे आर्थिक रूप से सशक्त बन गए हैं और बीमा, रुपे कार्ड, मोबाइल बैंकिंग एवं जीरो बैलेंस सुविधा सहित अन्य सभी बैंकिंग फायदों का लाभ उठा रहे हैं।

— वसुंधरा राजे

स्वच्छता को एक अभियान के रूप में लिया गया। हर घर में शौचालय बनाने की मुहिम से प्रदेश को स्वच्छता में पहला स्थान मिला।

— शिवराज सिंह चौहान

आज फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या किए जाने की घोषणा की तथा अयोध्या में निर्मित होने वाले मेडिकल कॉलेज को अयोध्या की परम्परा के अनुरूप राजा दशरथ जी के नाम पर तथा हवाई अड्डे को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम जी के नाम पर किए जाने की भी घोषणा की।

— योगी आदित्यनाथ

सभार : सोशल मीडिया

आत्मविश्वास से भरा है भारत

भारत ने एक बार पुनः एक बड़ी छलांग लगाते हुए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार में सुगमता) के पैमाने पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस वर्ष 23 पायदानों की छलांग लगाकर भारत अब विश्व में 77वें स्थान पर खड़ा है। यदि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पिछले चार वर्षों में हुए व्यापक सुधारों का इसे प्रतिफल माना जाये, तब सचमुच यह एक चमत्कार है। यूपीए शासन के दौरान जब पूरा देश नीतिगत पंगुता, भयंकर भ्रष्टाचार एवं कांग्रेस कुशासन से त्रस्त था, भारत की स्थिति इस पैमाने पर निरंतर बद से बदतर होती रही और 190 देशों की सूची में 2014 में 142वें स्थान पर देश पहुंच गया। पिछले चार वर्षों में भारत का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि यह पहले 130वें स्थान पर पहुंचा और पिछले दो वर्षों में 30 एवं 23 स्थानों की छलांग लगाकर अब 77वें स्थान पर है। भारत का प्रदर्शन 10 में से 6 क्षेत्रों में जबरदस्त रहा, जिस कारण देश का आर्थिक वातावरण में जबरदस्त सुधार हुआ है। भारत ने कारोबार शुरू करने में आसानी हेतु, निर्माण अनुमति, बिजली, ऋण प्राप्ति, कर अदायगी, सीमा पार व्यापार एवं अनुबंध की सुनिश्चितता के पैमाने पर अपनी स्थिति अत्यधिक मजबूत कर ली है। यह आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के उदय का प्रतीक है, जिसका नेतृत्व कड़े निर्णय ले सकता है तथा पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सकता है।

एक ओर जब स्मारकों से हर भारतीय देश के विकास में अपनी शक्तिभर योगदान करने को प्रेरित हो रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है।

अब जबकि भारत सुशासन एवं विकास के सभी मानदंडों पर खरा उतर रहा है, 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के अनावरण से भारत की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल, जिन्होंने अपने विलक्षण नेतृत्व क्षमता से पूरे देश का एकीकरण किया, के प्रति देश की एक विनम्र श्रद्धांजलि है। गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के बीच खड़ी 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' आज विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे, हर भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो रहा था और देश के इस महान् विभूति को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। यह एक ऐसा अवसर था जिसका उत्सव पूरा देश मना रहा था तथा हर भारतीय के मन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के सुनहरे भविष्य के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हो रहा था। यह एक ऐसा समय था जब पूरा देश एकजुट होकर देश की एकता एवं अखंडता के लिये समर्पित होने को पुनः शपथ ले रहा था। विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' न केवल सरदार पटेल के असाधारण योगदानों का स्मरण दिलाती रहेगी, बल्कि देश की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध खड़ी विभाजक एवं विनाशकारी तत्वों के विरुद्ध हर देशवासी को सजग एवं एकजुट रहने की भी प्रेरणा देती रहेगी।

स्मारक, संग्रहालय एवं मूर्तियां न केवल महान् विभूतियों के प्रति जनमानस की विनम्र श्रद्धांजलि होती है, बल्कि पूरा राष्ट्र इनसे इनके सिद्धांतों एवं मूल्यों पर चलने के लिए प्रेरणा पाता है। विश्व की सबसे ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में सरदार पटेल को समर्पित एक संग्रहालय, गांधी नगर में महात्मा मंदिर एवं दाण्डी कुटीर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित पंचतीर्थ, हरियाणा में श्री छोटूराम की मूर्ति, कच्छ में वीर नायक गोविंद गुरु एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के स्मारक के निर्माण कार्य को भी सुनिश्चित किया है। दिल्ली में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को समर्पित एक संग्रहालय, मुंबई में वीर शिवाजी की प्रतिमा और देश भर में जनजातीय संग्रहालयों का भी निर्माण कार्य चल रहा है। नये भारत का निर्माण जहां 'अंत्योदय' के मंत्र से अभिमंत्रित है, वहीं गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला एवं युवा के लिए विशेष कार्ययोजना से हो रहे व्यापक बदलाव को पूरा विश्व अचम्भे से देख रहा है। एक ओर जब स्मारकों से हर भारतीय देश के विकास में अपनी शक्तिभर योगदान करने को प्रेरित हो रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' राष्ट्र को समर्पित

भारत ने भविष्य के लिए प्रेरणा का आधार तैयार किया: नरेन्द्र मोदी

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को उनकी 143 वीं जयंती पर राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया। 'स्टैच्यू आफ यूनिटी' जहां राष्ट्रीय गौरव और एकता की प्रतीक है, वहीं यह भारत के इंजीनियरिंग कौशल तथा परियोजना प्रबंधन क्षमताओं का सम्मान भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को राष्ट्र को समर्पित किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 143 वीं जयंती पर 182 मीटर की उनकी प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में राष्ट्र को समर्पित की गई। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के लोकार्पण के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल श्री ओ. पी. कोहली और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी मौजूद थे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मिट्टी और नर्मदा नदी के पानी को कलश में भरकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर प्रतिमा के वर्चुअल अभिषेक की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री ने वॉल ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के नीचे प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा की। प्रधानमंत्री ने संग्रहालय तथा प्रदर्शनी और दर्शक दीर्घा को भी देखा। यह दीर्घा 153 मीटर ऊंची है और एक साथ इसे 200 आगुंतक देख सकते है। यहां से सरदार सरोवर बांध, इसके जलाशय तथा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत शृंखलाओं का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस समारोह में भारतीय वायु सेना के विमान और सांस्कृतिक दस्तों ने करतब दिखाए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में विशेष महत्व का दिन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के साथ भारत ने आज भविष्य के लिए स्वयं को विशाल प्रेरणा दी है।

प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को भारत के शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरदार पटेल ने सैकड़ों रियासतों का विलय कर और देश का एकीकरण करके इसे तोड़ने की साजिश को परास्त करने का काम किया। श्री मोदी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने की हर तरह की कोशिश का पुरजोर जवाब दें। इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना है। समाज के तौर पर एकजुट रहना है।

उन्होंने कहा कि आज देश के लिए सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है, जिसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। देश की

एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है, जो सरदार पटेल देकर गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार तो मैं हैरान रह जाता हूं, जब देश में ही कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति से जोड़कर देखते हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है मानो हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उन्होंने जोर दिया कि करोड़ों भारतीयों की तरह उनके मन में एक ही भावना थी कि जिस व्यक्ति ने देश को एक करने के लिए इतना बड़ा पुरुषार्थ किया हो, उसको वो सम्मान अवश्य मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है।

देश के एकीकरण में सरदार पटेल के योगदान को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिस कमज़ोरी पर दुनिया उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा वह भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है। दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को यह याद दिलाने के लिए है कि ये राष्ट्र शाश्वत था, शाश्वत है और शाश्वत रहेगा।

श्री मोदी ने कहा कि सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया था, जब देश साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों में बंटी थी। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधताओं की वजह से ही बिखर जाएगा।

आज देश के लिए सोचने वाले युवाओं की शक्ति हमारे पास है। देश के विकास के लिए यही एक रास्ता है, जिसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। देश की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखना एक ऐसा दायित्व है, जो सरदार पटेल देकर गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए उन्होंने अपने राज्यों का विलय कर दिया। देखते ही देखते, भारत एक हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ से कोहिमा तक, करगिल से कन्याकुमारी तक आज अगर बेरोकटोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने संकल्प न लिया होता, तो आज गिर के शेर को देखने के लिए, सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद चार मीनार को देखने के लिए वीज़ा लेना पड़ता। उनका संकल्प न होता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

श्री मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र से सामान्य जन को जोड़ने के लिए वह समर्पित रहे। महिलाओं को भारत की राजनीति में सक्रिय योगदान का अधिकार देने के पीछे भी सरदार पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल चाहते थे कि भारत सशक्त, सुदृढ़, संवेदनशील, सतर्क और समावेशी बने। हमारे सारे प्रयास उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का ये स्मारक उनके प्रति करोड़ों भारतीयों के सम्मान, हमारे सामर्थ्य का प्रतीक तो है ही, ये देश की अर्थव्यवस्था, रोज़गार निर्माण का भी महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। इससे हज़ारों आदिवासियों को हर वर्ष सीधा रोज़गार मिलने वाला है।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सरकार की जन कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। इसमें गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने, शौचालयों का निर्माण, हर बेघर को पक्का घर, गांव-गांव में बिजली सुविधा मुहैया कराने की पहल शामिल है। उन्होंने प्रतिमा के निर्माण में शामिल कामगारों, शिल्पकारों तथा शिल्पकार श्री राम सुतार की टीम को धन्यवाद दिया।

उल्लेखनीय है कि यह प्रतिमा अमेरिका में स्थित 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' से करीब दो गुनी ऊंची है और गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक छोटे द्वीप पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 70,000 टन से ज्यादा सीमेंट, 18,500 टन री-एंफोर्समेंट स्टील, 6,000 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन कांसा का इस्तेमाल हुआ है। ■

जो कोई भारत को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जायेगा: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 28 अक्टूबर को परेड ग्राउंड, सिकंदराबाद (तेलंगाना) में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित "विजय लक्ष्य - 2019, युवा महाधिवेशन" को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज युवा महाकुंभ के इस अद्भुत दृश्य को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि 2019 में देश के आम चुनाव का परिणाम निश्चित है। 2014 से भी अधिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि दो दिन बाद 31 अक्टूबर को देश की एकता एवं अखंडता के प्रणेता सरदार पटेल जी की जन्मजयंती है और उसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की यही वह पवित्र भूमि है जहां सरदार पटेल ने सिंहनाद किया था कि जो भारत में नहीं रहना चाहते, उसकी भारत में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां के वीर जवानों ने निजाम और उसकी रजाकारों के अत्याचार का डट कर सामना किया था और जब सरदार पटेल यहां आये तो रजाकारों को दुम दबाकर भागना पड़ा।

श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रजाकारों के भयानक जुल्म के खिलाफ यहां की जनता ने जो बलिदान दिया, उनके सम्मान में 17 सितंबर को प्रति वर्ष 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाया जाता है लेकिन एआईएमआईएम और ओवैसी के डर से टीआरएस सरकार ने 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' मनाना बंद कर दिया, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि अब तेलंगाना सरकार के गिने-चुने दिन ही बाकी हैं। तेलंगाना में भी सरकार बदलने वाली है और श्री नरेन्द्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' का भव्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे और देश की अखंडता के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था - 'तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा'। आज देश आजाद है। जब देश की आजादी के लिए बलिदान देने का वक्त था, हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अब वक्त है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के पुनर्निर्माण के लिए काम करने का। उन्होंने हमारे सामने दो विकल्प हैं - एक ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई गाथा लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी ओर ऐसा महागठबंधन जिसका न तो कोई नेता है, न नीति है, न नीयत है और न ही कोई सिद्धांत। हम ऐसे हाथों में देश की बागडोर सौंपने की भूल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के नवनिर्माण के लिए एकजुट हो जाना चाहिए।

कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी आये दिन कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार साल में क्या किया? अरे राहुल गांधी, आपकी चार

पीढ़ियों ने देश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और आप अपने पल-पल और क्षण-क्षण का हिसाब देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं! उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के सभी झूठे हथकंडों से वाकिफ है और वह आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 55 सालों से अभी अधिक समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश की लगभग 50 करोड़ की आबादी बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 32 करोड़ जन-धन खाते खोले गए, लगभग पांच करोड़ गरीब माताओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, 7.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, 2 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, गरीबों के लिए दो करोड़ पक्के मकान बनाए गए, 13 करोड़ बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया और लगभग 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने से पहले अपनी सरकारों का इतिहास देख लेना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राज्य के हर गांव में 24 घंटे बिजली, हर घर में गैस, हर घर में शौचालय, हर गांव तक सड़क और पीने का पानी पहुंचा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत मूल्य का डेढ़ गुना करने का निर्णय लिया है। साथ ही गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान भारत योजना भी लागू की गई है ताकि गरीबों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त मिल सके।

मोदी-विरोध की धुरी पर अवसरवादी दलों की महागठबंधन की तलाश पर कटाक्ष करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि महागठबंधन केवल एक ढकोसला मात्र है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल नेताओं का उद्देश्य न तो देश से गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को हटाना है और न ही देश के दुश्मनों को हराना है। उनका एकमात्र एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हराना है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों और इनके नेताओं के एजेंडे में देश कहीं है ही नहीं। जिनके एजेंडे में केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर जनता का वोट हड़पना हो, ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता भला देश का विकास क्या कर पायेंगे! उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'मेक इन इंडिया' के लिए काम करते हैं, तो कांग्रेस एंड कंपनी 'ब्रेक इन इंडिया' के लिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महागठबंधन का कोई जनाधार नहीं है, इससे चुनाव परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे सब एक होकर क्यों न प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ लड़ें, लेकिन देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी जीत का दिवास्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के लोक सभा चुनावों के बाद देश में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार। आने वाले पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव और 2019 के लोक सभा चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार निश्चित है।

राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक विधान सभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनके गठबंधन को बहुमत मिलने पर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी की बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राहुल गांधी, आपके गठबंधन के नेता तो आपको अपना नेता पहले से ही नहीं मानते हैं, अब तो आपकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी यह कह दिया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं हैं।

कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो समझ ही नहीं आता, कभी वह जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है तो कभी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वालों के साथ। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो कोई भी भारतवर्ष को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, उसे क़ानून के हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र तो समझ ही नहीं आता, कभी वह जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है तो कभी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने वालों के साथ। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो कोई भी भारतवर्ष को तोड़ने का षड्यंत्र करेगा, उसे क़ानून के हिसाब से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया जैसे कई योजनाओं को धरातल पर उतार कर युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब क्रियेटर बनाने का कार्य किया है। उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आपको आरोपों का जवाब परिश्रम से देना है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूनम महाजन जी के नेतृत्व में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को उन तक पहुंचाएं। ■

'हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेगा'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 27 अक्टूबर को कुन्नूर, केरल में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए इस अवसर पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर भारत की महान परम्परा और संस्कृति का अपमान का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पी. विजयन को भगवान् अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार बंद करने की चेतावनी दी।

श्री शाह ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कुन्नूर में पार्टी का कार्यालय आज सबके सामने है जो हमारी विचारधारा का स्तंभ है। उन्होंने कहा कि कुन्नूर में हमारे 120 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का निरंतर संघर्ष किया है। हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान भारत को पुनः विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित करेगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में आस्था, श्रद्धा और धर्म पर कम्युनिस्ट पार्टी की विजयन सरकार का दमन चक्र चल रहा है। केरल की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा राज्य में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए गए

हैं। उन्होंने कहा कि केरल में भक्त, श्रद्धालु और राज्य की जनता अपनी आस्था और परम्पराओं की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है जबकि केरल की कम्युनिस्ट सरकार उन पर दमन का कुचक्र चला रही है। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजयन सरकार ने अब तक भाजपा, हमारे विचार परिवार और हमारी सहयोगी संस्थाओं के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गलत प्रकार से डैमेज ऑफ़ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट में फंसाकर जेल में डाल दिया है।

श्री शाह ने कहा कि आर्टिकल 14 की दुहाई दी जाती है, जबकि आर्टिकल 25 और 26 में मुझे भी अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। आखिर एक फंडामेंटल राईट दूसरे फंडामेंटल राईट को ओवरराईट कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा कि कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट हुए हैं जिनका आज तक अमल ही नहीं हो पाया। जल्ली-कट्टू, मस्जिदों पर माइक से अजान, दही-हांडी में हाईट रेस्ट्रिक्शन, बनारस में शिया-सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद और भगवान् स्वामी पद्मनाभ के सातवें द्वार को खोलने के जजमेंट पर आज तक अमल नहीं हो पाया। केरल के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते उन्होंने कहा कि क्या केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन सुप्रीम कोर्ट के मस्जिदों में माइक पर अजान के जजमेंट को लागू करेंगे? क्या उन्हें ऐसा कर पाने का साहस है? जब पी. विजयन ऐसा नहीं कर सकते तो फिर भगवान् अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है?

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी संस्कृति में और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं को पूजनीय माना गया है। हम महिलाओं को देवी और भगवती के रूप में पूजते हैं। हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान और आदर किया है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में कई प्रकार की परम्पराएं हैं। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अलग-अलग मान्यताओं एवं परम्पराओं के आधार पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में कई ऐसे मंदिर हैं जहां केवल महिलाओं का प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। स्त्री-पुरुष समानता किसी मंदिर में दर्शन से नहीं आती है। हमने बाल-विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह जैसे कई सामाजिक सुधार स्वयं किये। सबरीमाला में भगवान् अयप्पा के ब्रह्मचर्य स्वरूप की पूजा होती है, इसलिए हमें यहां की आस्था और परम्पराओं का भी सम्मान करना चाहिए। केरल की माताएं-बहनें स्वयं कह रही हैं कि 10 से 50 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं का प्रवेश सबरीमाला में नहीं होना चाहिए और कम्युनिस्ट सरकार भगवान् अयप्पा के भक्तों पर वीभत्स अत्याचार कर रही है।

श्री शाह ने कहा कि जहां आस्था का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। उन्होंने विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम्युनिस्ट सरकार जितना ध्यान भगवान् अयप्पा के भक्तों पर अत्याचार करने में लगा रही है, उतना ध्यान यदि केरल की जनता की भलाई के लिए लगाती तो आज राज्य के किसानों की यह हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि केरल में केंद्र सरकार ने विकास की कई परियोजनाएं दी हैं, लेकिन उन योजनाओं को पूरा करने के लिए तो मुख्यमंत्री पी विजयन के पास समय नहीं है, लेकिन भगवान् अयप्पा के भक्तों पर दमनचक्र चलाने के लिए उनके पास पूरा समय है। उन्होंने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन को एक पल भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।

उन्होंने केरल की जनता से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि भारत की महान संस्कृति, धर्म, आस्था और परम्पराओं की रक्षा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को 59 मिनट में मिलेगा एक करोड़ तक का कर्ज

प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं

देश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर को कई सुविधाएं दी। इस क्षेत्र की इकाइयों को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक कर्ज उपलब्ध कराने के लिये आनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज वह जिन 12 निर्णयों की घोषणा कर रहे हैं, वे एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय साबित होंगे।

ऋणों तक पहुंच

प्रथम घोषणा के रूप में श्री मोदी ने एमएसएमई को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट के लोन पोर्टल का शुभारंभ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है।

श्री मोदी ने दूसरी घोषणा के रूप में सभी जीएसटी पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने का उल्लेख किया। शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए प्रधानमंत्री ने ब्याज की छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री की तीसरी घोषणा यह थी कि पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को अब आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियां ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) पोर्टल में शामिल किया जाए।

बाजारों तक पहुंच

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों की बाजार तक पहुंच के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने चौथी घोषणा यह की कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी की 25 प्रतिशत खरीदारी एमएसएमई से करने के लिए कहा गया है।

प्रधानमंत्री की पांचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

उन्होंने छठी घोषणा यह की है कि केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से जीईएम का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को जीईएम से पंजीकृत कराना चाहिए। श्री मोदी की सातवीं घोषणा यह थी कि पूरे देश में 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किए जाएंगे।

कारोबार में सुगमता

कारोबार की सुगमता के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि उनकी 8वीं घोषणा फार्मा कंपनियों के बारे में है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। उन्होंने कहा कि 9वीं घोषणा यह है कि आठ श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत रिटर्न अब साल में एक ही बार फाइल किये जायेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि 10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इकाई स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों को दो क्लीयरेंस की जरूरत होती है- पर्यावरण क्लीयरेंस और इकाई स्थापित करने की रजामंदी। उन्होंने कहा कि 11वीं घोषणा यह है कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिटर्न, स्व–प्रमाणीकरण के जरिये स्वीकार किया जायेगा।

12वीं घोषणा के रूप में प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिए उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जायेगा। ■

प्रधानमंत्री द्वारा 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं

- सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 59 मिनट का लोन पोर्टल
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एमएसएमई से 25 प्रतिशत की खरीदारी करना अनिवार्य होगा
- कंपनी अधिनियम के तहत छोटे आर्थिक अपराधों से जुड़ी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए अध्यादेश

भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में 23 पायदानों की और ऊंची छलांग

वर्ष 2017 के 100वें पायदान से सुधरकर अब 77वें पायदान पर

विश्व बैंक ने 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपनी नवीनतम 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर, 2019)' जारी की। भारत ने 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में 23 पायदानों की और ऊंची छलांग लगाई। विश्व बैंक द्वारा आकलन किये गये 190 देशों वाली 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' में भारत वर्ष 2017 के 100वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब 77वें पायदान पर पहुंच गया। भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊंची छलांग निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबर्दस्त छलांग लगाई थी, जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। सरकार द्वारा किये गये निरन्तर प्रयासों की बदौलत 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों में 65 पायदान ऊपर चढ़ गया है।

'डूइंग बिजनेस आकलन' से उन 10 पैमानों पर 190 देशों में व्यवसाय या बिजनेस संबंधी नियम-कायदों और उन पर अमल के वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों के बारे में पता चलता है, जो किसी भी व्यवसाय के समूचे कारोबारी चक्र पर असर डालते हैं। डीबीआर में देशों की रैंकिंग 'डिस्टैंस टू फ्रंटियर (डीटीएफ)' के आधार पर की जाती है जो एक विशिष्ट स्कोर है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनाये जाने वाले कारोबारी तौर-तरीकों और वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों में अंतर को दर्शाता है। भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले वर्ष के 60.76 से बढ़कर इस वर्ष 67.23 हो गया।

भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है और इसके साथ ही वह 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों के और करीब पहुंच गया। हालांकि, सबसे उल्लेखनीय सुधार 'निर्माण परमिट' और 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में देखा गया।

निर्माण परमिट की स्वीकृति देने के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 181वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 52वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 129 रैंकिंग के अभूतपूर्व सुधार को दर्शाता है। इसी तरह 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 146वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 80वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 66 रैंकिंग के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है। जिन छह संकेतकों पर भारत ने अपनी रैंकिंग सुधारी है उनमें ये निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	संकेतक	2017	2018	सुधार
1	निर्माण परमिट	181	52	+129
2	सीमा पार व्यापार	146	80	+66
3	कोई कारोबार शुरू करना	156	137	+19
4	ऋण प्राप्त करना	29	22	+7
5	बिजली प्राप्त करना	29	24	+5
6	अनुबंधों पर अमल	164	163	+1
	समग्र रैंक	100	77	+23

इस वर्ष भारत के प्रदर्शन की मुख्य बातें निम्न हैं–

- विश्व बैंक ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत को भी शुमार किया है।
- उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत की भी गिनती लगातार दूसरे वर्ष की गई है।
- भारत प्रथम ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले शीर्ष देशों में लगातार दूसरे वर्ष शुमार किया गया है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में किये गये सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।
- प्रदर्शन में निरंतर सुधार की बदौलत भारत अब दक्षिण एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2014 में यह छठे स्थान पर था।

भारत के प्रदर्शन की संकेतक–वार मुख्य बातें निम्न हैं–

(क) प्रक्रियाओं की संख्या मुंबई में 37 से घटकर 20 और दिल्ली में 24 से घटकर 16 रह गई है।

(ख) इसमें लगने वाला समय मुंबई में 128.5 दिनों से घटकर 99 दिन और दिल्ली में 157.5 से घटकर 91 दिन रह गया है।

(ग) भवन निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण सूचकांक मुंबई में 12 से सुधरकर 14 और दिल्ली में 11 से सुधरकर 14 हो गया है।

(घ) निर्माण परमिट प्राप्त करने की लागत 23.2 प्रतिशत से घटकर 5.4 प्रतिशत रह गई है।

(ड.) डीटीएफ स्कोर 38.80 से सुधरकर 73.81 हो गया है। ■

आईएनएस अरिहन्त अपने पहले डेटरेंस पेट्रोल से लौटी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 नवंबर को भारत के स्ट्रेटजिक स्ट्राईक न्यूक्लियर सब्मरीन (SSBN) यानी नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस अरिहन्त के अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात की। आईएनएस अरिहन्त हाल ही में अपने पहले डेटरेंस पेट्रोल (निवारण गश्त) से लौटी है। पनडुब्बी के इस अभ्यास से भारत के नाभिकीय त्रिकोण की पूर्ण स्थापना हुई।

आईएनएस अरिहन्त के सफल अभियान से भारत के नाभिकीय त्रिकोण (nuclear triad) की स्थापना के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आईएनएस अरिहन्त के कर्मीदल तथा अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि भारत को उन गिने-चुने देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी करती है जो SSBN को डिज़ाइन करने, उसे बनाने और उसके संचालन करने की क्षमता रखते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि देश में ही SSBN के निर्माण और इसके सफल संचालन की क्षमता का विकास भारत की प्रोद्योगिकीय सामर्थ्य तथा सभी संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अभूतपूर्व समन्वय का प्रतीक है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को देश की सुरक्षा को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने वाली इस उपलब्धि के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि परमाणु परीक्षणों की वैज्ञानिक उपलब्धि को एक अत्यंत जटिल और विश्वसनीय नाभिकीय त्रिकोण में बदल पाने का अत्यंत दुष्कर कार्य भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अनवरत प्रयासों तथा बहादुर सैनिकों के साहस और समर्पण की भावना से ही संभव हुआ है। इस नई उपलब्धि ने भारत द्वारा नाभिकीय त्रिकोण स्थापित करने के लिए आवश्यक क्षमता और दृढ़ता के संबंध में उठाए जाने वाले सभी सवालों को खारिज कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग शक्तिमान भारत बनाने और नये भारत का निर्माण करने की आकांक्षा रखते हैं और इसके लिए भारतीयों ने अनवरत प्रयासों के द्वारा अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि एक सशक्त भारत न सिर्फ सवा सौ करोड़ से अधिक भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगा, बल्कि आज के अनिश्चिता तथा आशंकाओं से भरे विश्व में वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए आधार स्तंभ भी रहेगा।

श्री मोदी ने सभी उपस्थित व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ये आशा भी व्यक्त की जिस प्रकार प्रकाश अंधकार का ही निवारण नहीं करता बल्कि भय को भी दूर करता है, उसी प्रकार आईएनएस अरिहन्त भी देश को अभय करेगा।

एक ज़िम्मेदार राष्ट्र के रुप में भारत ने एक मजबूत न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल संरचना, प्रभावशाली सुरक्षा व्यवस्था और पूर्ण राजनैतिक नियंत्रण, देश की नाभिकीय कमांड प्राधिकरण (Nuclear Command Authority) के अधीन स्थापित किए हैं। प्रामाणिक न्यूनतम निवारण (Credible Minimum Deterrence) और परमाणु हथियारों के प्रथम इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने 4 जनवरी 2003 को निर्धारित की थी, के प्रति भारत प्रतिबद्ध है। ■

सांस्कृतिक अधिष्ठान

भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एकात्म मानववाद के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा 4 जून, 1959 को कानपुर में संपन्न संघ शिक्षा वर्ग में दिए गए बौद्धिक का अंतिम भाग:

दीनदयाल उपाध्याय

आज का कम्युनिज्म भी संपूर्ण मानव की एकता के लिए किए गए प्रयासों में से एक प्रयास है। यह प्रयास आज भी चल रहा है। जहां न धर्म है और न मज़हब है। साम्यवाद ही इनका मजहब है। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन तथा खुश्चेव इनके मसीहा हैं। मार्क्स और एंजिल्स के ग्रंथ इनके कुरान हैं। मार्क्स ने पूंजीवाद के अंदर ही क्रांति की भविष्यवाणी कर मानव एकता का एक स्वरूप वर्णित किया है। उसके अनुसार जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि औद्योगिक देशों से ही, जहां आर्थिक विषमता है, यह क्रांति प्रारंभ होने की थी, परंतु हमने देखा कि क्रांति एक ऐसे देश से प्रारंभ हुई, जहां जारशाही से पीड़ित होकर राष्ट्रीयता समाप्त हो चुकी थी और वह भी स्विट्जरलैंड में निर्वासित लेनिन के नेतृत्व में, जो विजेता देश से प्रेरणा प्राप्त किए हुए था। इनका प्रयास भी अपने इन विचारों के प्रसार के लिए आर्थिक विषमता का ही आधार लेकर खड़ा था। परंतु हमने यह भी देखा कि द्वितीय महायुद्ध में जब जापान की हार हो गई तो रूस के लोगों ने यह कहा कि आज जापान से बदला लेने की हमारी इच्छा बहुत दिनों में पूर्ण हुई। इस कथन में भी राष्ट्रीयता की झलक दिखाई पड़ती है।

क्योंकि सन् 1905 की हार के समय तो रूस की साम्यवादी विचारधारा थी ही नहीं, अतः द्वितीय महायुद्ध के परिणामों से बदले की भावना का क्या अर्थ? द्वितीय महायुद्ध में भी जर्मनी से हार के समय उस काल में रूस निवासियों के सामने साम्यवाद अथवा लेनिन और मार्क्सवाद के द्वारा प्रेरित विचार नहीं थे, अपितु रूस के उन्हीं पुराने पुरुषों तथा परंपराओं का सहारा लिया गया, जिनको साम्यवादी आए दिन कोसते रहते हैं। आज रूस द्वारा संचालित साम्यवाद के पीछे रूसी राष्ट्रीयता एवं विचार का ही आधार है। इनकी दृष्टि में राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं। शोषक व शोषित, अमीर व ग़रीब-यही दो वर्ग हैं।

अतः राष्ट्रवाद के स्थान पर विश्व एकता के लिए कोई दूसरा विचार संभव नहीं। जिन-जिन लोगों ने यह स्वप्न देखा, उन्होंने केवल मनुष्य के किसी एक अंग विशेष पर जोर दिया। उनमें से किसी ने पेट देखा, किसी ने रोटी देखी और किसी ने केवल मज़हब का नारा बुलंद कर सारे संसार को उसी के अनुसार बांधने का प्रयास किया। किसी ने ईश्वर के पैगंबर पर श्रद्धा रखकर ही सारे संसार को एक सूत्र में बांधना चाहा। किसी ने एक उपासना पद्धति देखी, किंतु इन सबका विचार करने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने मनुष्य का विचार केवल ऐकांतिक रूप में किया, केवल एक हस्ती के रूप में किया है।

परंतु मनुष्य में जिस प्रकार विविधता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र में भी होती है। मनुष्य के जिस प्रकार से विचार होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के भी विविध प्रकार के विचार होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को इसलिए अपनी विशेषताओं के आधार पर विकास करने को अवसर दिया जाना चाहिए। उसे अपनी विशिष्टताओं के आधार पर प्राकृतिक रूप से बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य को अपने पराक्रम करने का मौक़ा दिया जाए। उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार विकास का अवसर दिया जाए। संसार में जो संघर्ष है, हमें उसे मिटाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम संघर्ष को मिटाने के लिए सभी को मिटाकर उनकी विशिष्टताओं को समाप्त कर दें। वरन् उन सबको एक साथ प्रगति की ओर बढ़ाने की व्यवस्था करें। इसी विचार के आधार पर हमने यह सोचा और हमने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' को नारा बुलंद किया है।

इसी के अनुसार हमने सारी दुनिया को सभ्य बनाने का काम किया, इसके अनुसार हमने सारी दुनिया को आर्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का काम किया। इस प्रकार हमारा कभी भी किसी को हिंदू बनाने का तथा किसी को अपना विचार मनवाने का आग्रह नहीं रहा। अपनी-अपनी पद्धति के अनुसार सभी लोग अपने इच्छित गंतव्य की ओर बढ़ेंगे, ध्येय को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करेंगे। हम एक विचार करें कि आज हमारे देश की सेना तीन नामों के आधार पर संगठित है। पहली, वायु सेना व दूसरी स्थल सेना तथा तीसरी जल सेना है। इन तीनों टुकड़ियों में हर एक की अपनी-अपनी अलग विशेषता है। इनके विकास के रास्ते, अपने स्तर, उनके अपने आदर्श हैं व ध्येय हैं, जिनको प्राप्त करने का वे प्रयास करती हैं। उनकी अपनी विशेषता रहती है, जिसके आधार पर वे अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। वायु सेना का सैनिक स्थल सेना से यह कभी नहीं कहता कि तुम मेरे अनुसार चलो या वायु सेना के नियमों के अनुसार कार्य करो। स्थल सेना का सिपाही नौ सेना से यह कभी नहीं कहता कि तुम मेरी योजनानुसार काम करो। वे कभी भी अपने विचार या विशिष्टताओं को दूसरों पर लादना नहीं चाहते। परंतु जब देश को आवश्यकता पड़ती है कि देश की सारी सेनाएं देश की रक्षा करें, तो हम देखते हैं। कि सारी सेनाएं अपनी-अपनी विशिष्टताओं के साथ रक्षा करती हैं। सभी देश की रक्षा के लिए एकत्व भाव से एक शरीर के रूप में काम करती हैं और देश की रक्षा में उन सभी का अपना-अपना हाथ

होता है।

उसी प्रकार संसार के विभिन्न राष्ट्र भी अपनी विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। विकसित हो सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अपना-अपना स्तर, ध्येय, आदर्श हो सकते हैं। जिस प्रकार किसी देश की विभिन्न सेनाएं अपने देश की रक्षा के लिए अपनी विशिष्टताओं का प्रयोग करती हैं और प्रत्येक राष्ट्र की विभिन्नताओं के रहने पर भी उसी प्रकार संसार के सारे देश अपना विकास अपने ध्येय के आधार पर अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त श्रेष्ठताओं के आधार पर कर सकते हैं। हम अपनी-अपनी विशेषताओं को पहचानें और दुनिया में अपना-अपना काम करें। परंतु यह उसी समय हो सकता है, जब हम अपनी विशेषताओं पर खड़े रहेंगे। अपनी विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास करेंगे। यह उस समय नहीं हो सकेगा, जब हम अपनी विशेषताओं को भूलकर उनके आधार पर विकास न करना चाहें। ऐसी स्थिति में न तो हम किसी को सहयोग दे सकेंगे और न ही संसार की कोई सेवा कर सकेंगे।

मानव की एकता के नाम पर हम अपनी विशेषताओं को भूलकर त्याग करके हम मानव की एकता क़ायम नहीं कर सकते। इस प्रकार मानव की एकता के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी विशेषताओं के आधार पर खड़ा हो। आध्यात्मिक आधार पर हमें खड़ा होना है। आध्यात्मिक ज्ञान सारे संसार को देना है, लेकिन हमें संसार को ज्ञान देने के लिए अपने अंदर सामर्थ्य को प्राप्त करना होगा। बिना सामर्थ्य के हम संसार को उस आधार पर खड़ा नहीं कर सकते। हमारे देश का एक महान् संन्यासी कुछ समय पूर्व विदेशों को गया था। उसने वहां पर भारत के महान् दार्शनिकों के ज्ञान को बताया। उनके सामने वेदांत के सिद्धांतों का निरूपण किया। उन्हें वेदांत के पाठ पढ़ाए। इस देश के लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस देश का यह व्यक्ति है, उस देश में इतना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, इतना बड़ा दर्शन, इतने ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, फिर भी वह देश ग़रीब क्यों है, वह देश गुलाम क्यों है? वह देश दासता के बंधनों में क्यों जकड़ा हुआ है? इन सब बातों का विचार करके इन देश के लोगों ने उस महान् प्रचारक स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामीजी, आपका देश तो विचारों की दृष्टि से, आध्यात्मिकता के ज्ञान की दृष्टि से अत्यंत प्रगति प्राप्त किए हुए है। परंतु फिर उस देश में इतनी ग़रीबी क्यों है, वह इतना पिछड़ा और गुलाम क्यों है? स्वामीजी इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर क्यों नहीं दे सके।

स्वामी विवेकानंदजी ने इस प्रश्न पर बार-बार विचार किया और विचार करने के बाद उनको यह स्पष्ट लगा कि हमारा देश इतने उच्च गुणों के होते हुए भी पिछड़ा हुआ इसलिए है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है। शक्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम सामर्थ्य ही उत्पन्न करने का विचार किया। जब तक हम हिंदुस्थान को सामर्थ्यवान नहीं बनाते, भौतिकता की दृष्टि से सबल नहीं होते, तब तक संसार को इस आधार पर नहीं खड़ा कर सकते। अपने उन उच्च सिद्धांतों की क़ीमत उसी समय होगी, जब हमें वह सामर्थ्य प्राप्त होगी, जिससे हम खड़े होकर एक ऊंचे मंच से जोरदार स्वर में कह सकेंगे कि हमारे पास ऐसे उच्च जीवनयापन के सिद्धांत हैं और सामर्थ्य के आधार पर हम उनको अपने जीवन में प्रकट भी करते हैं। इसीलिए इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए किसी कवि ने भारत के युवकों को यह चुनौती दी कि मर्द बनकर पहले हिंदुस्थान के वास्ते जागो, उसके बाद सारे जहां के वास्ते जागो। कविता के द्वारा कवि ने इस ओर इंगित किया है, जब हम सामर्थ्यवान होंगे, तभी संसार की सेवा कर सकेंगे अन्यथा नहीं। इसलिए आज परम आवश्यकता यह है कि हम सामर्थ्य प्राप्त करें।

संघ ने भी यही विचार किया और इस विचार के अनुसार काम भी करना प्रारंभ किया। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम बड़े होते चले जाएं। लोक-संग्रह का कार्य करें। सामर्थ्य के होने के बाद भी हम संसार की सेवा कर सकेंगे। सामर्थ्यवान जब परार्थ भाव से कोई काम करता है तो हम उसे सेवा कहते हैं। सेवा वही कर सकता है, जिसके पास इनकार करने की शक्ति हो, जो यह कह सके कि मैं यह काम नहीं करूंगा। वैसा व्यक्ति जब कोई परमार्थ करता है तो उसको हम सेवा कहते हैं। परंतु जब कोई कमज़ोर सेवा करता है तो वह सेवा नहीं होती, बेगार होती है, क्योंकि कमज़ोर के पास सामर्थ्य का अभाव होता है। इसलिए काम करते समय उसकी स्वयं की इच्छा का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि कमज़ोर से तो आवश्यकता होने पर भी सेवा कराई जा सकती है। यदि कमजोर जबरदस्ती कराए गए काम को कहता है कि मैंने सेवा की, तो यह बेगार है।

सामर्थ्यवान जब सेवा करता है तो लोग उसे कहते हैं कि उसने सेवा की। राष्ट्र की सेवा में केवल गुणों का ही आह्वान नहीं, वरन् हमें सामर्थ्य का भी आह्वान करना है। वह आह्वान राष्ट्रभाव के आधार पर होगा। मातृभूमि में चैतन्य को उत्पन्न करते हुए हमें प्रगति के मार्ग पर सामर्थ्य के साथ बढ़ना है और हम सब इसी आधार पर विश्वयज्ञ में मानव एकता के लिए आहुति देने को आगे बढ़ सकेंगे। संघ यही कार्य कर रहा है।

सामर्थ्यवान जब सेवा करता है तो लोग उसे कहते हैं कि उसने सेवा की। राष्ट्र की सेवा में केवल गुणों का ही आह्वान नहीं, वरन् हमें सामर्थ्य का भी आह्वान करना है। वह आह्वान राष्ट्रभाव के आधार पर होगा। मातृभूमि में चैतन्य को उत्पन्न करते हुए हमें प्रगति के मार्ग पर सामर्थ्य के साथ बढ़ना है और हम सब इसी आधार पर विश्वयज्ञ में मानव एकता के लिए आहुति देने को आगे बढ़ सकेंगे। संघ यही कार्य कर रहा है। संघ का कार्य केवल गुणों का आह्वान करना ही नहीं, बल्कि लोक सामर्थ्य का भी निर्माण करना है, जिससे राष्ट्र जीवन के ध्येय को हम संसार में प्रतिष्ठित कर सकें। हमारा संघ यही कार्य करता है। भगवान् हमें संघ कार्य करने के लिए सामर्थ्य दे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। ■

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना नहीं रहे

(15 अक्टूबर 1936 – 27 अक्टूबर 2018)

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदनलाल खुराना का 27 अक्टूबर को निधन हो गया। 82 वर्ष के श्री खुराना 1993 से लेकर 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें 2004 में राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। श्री मदनलाल खुराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे।

श्री खुराना का जन्म 15 अक्टूबर 1936 में पाकिस्तान के लैयलपुर जिसे अब फैसलाबाद के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। वह महज 12 वर्ष के थे जब बंटवारे की वजह से उनके परिवार को दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली आने के बाद श्री खुराना के परिवार को कुछ दिनों तक एक शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। श्री खुराना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर की डिग्री ली। वह 1959 में पहली बार छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और उन्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का महामंत्री चुना गया। इसके बाद वह 1960 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री चुने गए।

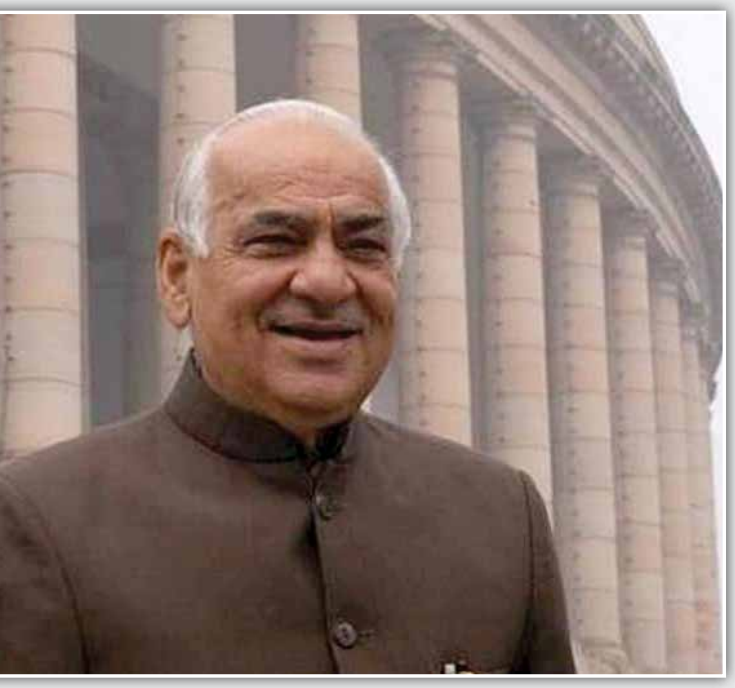

राजनीति में प्रवेश करने से पहले श्री मदन लाल खुराना दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, श्री केदारनाथ साहनी जैसे नेताओं के साथ मिलकर श्री खुराना ने दिल्ली में जनसंघ को स्थापित किया। वह 1965 से 67 तक जनसंघ के महामंत्री रहे।

पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने और कर्मठता की वजह से श्री खुराना को दिल्ली का शेर कहा जाता था। श्री मदनलाल खुराना 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 1996 तक इस पद पर रहे। श्री खुराना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। वह 14 जनवरी से 28 अक्टूबर 2004 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। ■

शोक सन्देश

श्री मदन लाल खुराना जी के निधन से दु:खी हूं। उन्होंने दिल्ली की प्रगति के लिए, विशेष रूप से बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर काम किया। उन्होंने खुद को दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों जगहों पर मेहनती और लोगों के अनुकूल काम करने वाले प्रशासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्री मदन लाल खुराना जी को हम हमेशा दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने के लिए याद करेंगे। उन्होंने विभाजन के बाद दिल्ली में शरणार्थियों की सेवा के लिए अविश्वसनीय कार्य किए। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना और एकजुटता है।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मदनलाल खुराना जी के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। खुराना जी एक आदर्श स्वयंसेवक, एक समर्पित विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता व जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तम्भ के रूप में सदैव याद किये जायेंगे। दिल्ली में संगठन को गढ़ने में खुराना जी की अहम भूमिका रही और वह 'दिल्ली के शेर' के रूप में सुप्रसिद्ध हुए। भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से खुराना जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त करता हूं व दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ॐ शांति शांति शांति।

— अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

'भारत एक मजबूत अर्थतंत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर को विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease of Doing Business) में भारत की रैंकिंग में ऐतिहासिक उछाल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई दी और कहा कि आज भारत एक व्यापार अनुकूल राष्ट्र व एक मजबूत अर्थतंत्र के साथ-साथ एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। श्री मोदी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व में भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

श्री शाह ने कहा कि जहां एक तरफ अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने भारत की रैंकिंग को 132 से गिराकर 142 कर दिया था, वहीं दूसरी ओर मोदी जी की परिवर्तनकारी नीतियों ने भारत को 142वें स्थान से 77वें स्थान पर लाकर विश्व पटल पर देश की साख स्थापित की। पिछले वर्ष भारत ने 30 अंकों की उछाल के साथ 100वां स्थान हासिल किया था। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस में भारत की रैंकिंग में लंबी छलांग हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किये जा रहे आर्थिक सुधारों का असर अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। ज्ञात हो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनस रैंकिंग्स में भारत ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करते हुए 23 अंकों की उछाल के साथ 77वां स्थान हासिल कर लिया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग्स में भारत की यह अभूतपूर्व उछाल मोदी सरकार द्वारा किए गए श्रृंखलाबद्ध नीतिगत सुधारों का परिणाम है जिसने देश में उद्योग, इनोवेशन और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले माहौल के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जब व्यवसाय करना आसान हो जाता है, तो कई युवाओं को अपने उद्यमशीलता कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर और समर्थन मिलता है। हमें इस बात की खुशी है कि यह सब पिछले चार वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इससे हमारे उभरते युवा और आत्मनिर्भर उद्यमियों को और अधिक ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रक्रियाओं को काफी सरल बनाया है। साथ ही, भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर भारी अंकुश लगा है। यह सब देश के विकास की तेज गति के लिए अच्छा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग्स भारत की रैंकिंग कई वर्षों से लगभग 130 के आसपास स्थिर रही, जबकि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान तो यह 142 तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीन साल की अवधि में ही इतना त्वरित और इतना बड़ा अंतर स्पष्ट रूप से सुशासन और सुधारों को बिना किसी चूक के लागू किये जाने को रेखांकित करते हैं।

श्री शाह ने कहा कि केंद्र में 10 वर्षों तक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की सरकार रही, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक पायदान का भी सुधार नहीं हो पाया। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत चार साल में ही अर्थव्यवस्था में 9वें पायदान से 6ठें स्थान पर पहुंची है और 2019 के लोक सभा चुनाव से पहले-पहले भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश ने कांग्रेस की सरकार के समय एक दौर ऐसा भी देखा है, जब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था। इस ग्रुप का नाम था- फ्रेजाइल फाइव जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल पार्टी या सरकार का कहना नहीं है, बल्कि मूडीज, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और नेमुरा जैसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियां इसकी तसदीक कर रही हैं। ■

व्यापार सुगमता रैंकिंग में भारत की ऐतिहासिक बढ़त के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी

विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री जिम योंग किम ने 2 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की और व्यापार सुगमता रैंकिंग में भारत की ऐतिहासिक बढ़त के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि 1.25 अरब से अधिक की जनसंख्या वाले एक देश ने चार वर्षों की छोटी अवधि में 65 रैंक की वृद्धि हासिल की है।

श्री किम ने इसे एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की अविश्वसनीय वचनबद्धता और कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। विश्व बैंक के अध्यक्ष ने श्री मोदी को हाल के समय में मिले सम्मानों को भी याद किया, जिनमें यूएनईपी का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड और सियोल शांति पुरस्कार शामिल थे। उन्होंने इन पुरस्कारों के लिए भी प्रधानमंत्री को बधाई दी।

श्री किम ने कारोबारी माहौल सुगम बनाने में भारत द्वारा की गई पहल को विश्व बैंक की और से निरंतर समर्थन दिए जाने का वादा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कारोबारी सुगमता बेहतर बनाने के भारत के प्रयासों में निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की और से दी गई रैंकिंग कारोबारी माहौल सुधारने के भारत के प्रयासों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ■

राष्ट्रवाद से एकता का भूगोल रचने वाले पटेल

नरेन्द्र मोदी

वर्ष 1947 के पहले छह महीने भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। साम्राज्यवादी शासन के साथ भारत का विभाजन भी अंतिम चरण में पहुंच गया था। हालांकि, उस समय यह तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं थी कि क्या देश का एक से अधिक बार विभाजन होगा। कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं, खाद्य पदार्थों की कमी आम थी, लेकिन इन बातों से परे सबसे बड़ी चिंता भारत की एकता को लेकर नज़र आ रही थी, जो खतरे में थी।

इस पृष्ठभूमि में 1947 के जून माह में 'गृह विभाग' का गठन किया गया। इस विभाग का प्रमुख लक्ष्य उन 550 से भी अधिक रियासतों से भारत के साथ उनके रिश्तों के बारे में बातचीत करना था, जिनके आकार, आबादी, भू-भाग अथवा आर्थिक स्थितियों में काफी भिन्नताएं थीं। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, ''राज्यों की समस्याएं इतनी विकट है कि सिर्फ 'आप' ही इसे सुलझा सकते हैं।'' यहां पर 'आप' से आशय किसी और से नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से था, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं और जिन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

अपनी विशिष्ट सरदार पटेल शैली में उन्होंने दृढ़ता और प्रशासनिक दक्षता के साथ इस चुनौती को पूरा किया। समय कम था और जवाबदेही बहुत बड़ी थी, लेकिन सरदार पटेल दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि वे किसी भी सूरत में अपने राष्ट्र को झुकने नहीं देंगे। उन्होंने और उनकी टीम ने एक-एक करके सभी रियासतों से बातचीत की और सभी को 'आजाद भारत' का अभिन्न हिस्सा बनाना सुनिश्चित किया।

सरदार पटेल ने पूरी तन्मयता और लगन से दिन-रात एक करते हुए इस कार्य को पूरा किया और इसी शैली की बदौलत ही आधुनिक भारत का वर्तमान एकीकृत मानचित्र हम देख रहे हैं। कहा जाता है कि वीपी मेनन ने स्वतंत्रता मिलने पर सरकारी सेवा से अवकाश लेने की इच्छा व्यक्त की। इस पर सरदार पटेल ने उनसे कहा कि समय आराम करने या सेवानिवृत्त होने का नहीं है। सरदार पटेल का ऐसा दृढ़ संकल्प था। वीपी मेनन विदेश विभाग के सचिव बनाए गए।

उन्होंने अपनी पुस्तक 'द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स' में लिखा है कि किस तरह सरदार पटेल ने इस मुहिम में अग्रणी भूमिका निभाई और अपने नेतृत्व में किस प्रकार पूरी टीम को परिश्रम से काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा है कि सरदार पटेल के लिए सबसे पहले भारत की जनता के हित थे, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

हमने 15 अगस्त 1947 को नए भारत के उदय का उत्सव मनाया, लेकिन राष्ट्र निर्माण का कार्य अधूरा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक ढांचा बनाने का काम प्रारंभ किया, जो आज भी जारी है- चाहे यह दैनिक शासन संचालन का मामला हो अथवा गरीब और वंचित लोगों के हितों की रक्षा का मामला हो। सरदार पटेल अनुभवी प्रशासक थे। प्रशासन में

उनका अनुभव विशेषकर 1920 के दशक में अहमदाबाद नगरपालिका में उनकी सेवा का अनुभव, स्वतंत्र भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक साबित हुआ।

उन्होंने अहमदाबाद में स्वच्छता और जल निकासी प्रणाली सुनिश्चित की। आज यदि भारत जीवंत सहकारिता क्षेत्र के लिए जाना जाता है तो इसका श्रेय सरदार पटेल को है। ग्रामीण समुदायों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने का उनका विज़न अमूल परियोजना में दिखता है। ये सरदार पटेल ही थे, जिन्होंने सहकारी आवास सोसाइटी के विचार को लोकप्रिय बनाया और इस प्रकार अनेक लोगों के लिए सम्मान और आश्रय सुनिश्चित किया।

भारत के किसानों की उनमें प्रगाढ़ आस्था थी। वे किसान पुत्र थे, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह के दौरान अगली कतार से नेतृत्व किया। श्रमिक वर्ग उनमें ऐसा नेता देखता था जो उनके लिए बोलेगा। व्यापारी और उद्योगपतियों ने उनके साथ इसलिए काम करना पसंद किया, क्योंकि वे समझते थे कि सरदार पटेल भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के विज़न वाले दिग्गज नेता हैं। उनके राजनीतिक मित्र भी उन पर भरोसा करते थे।

आचार्य कृपलानी का कहना था कि जब कभी वे किसी दुविधा में होते थे और यदि बापू का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था तो वे सरदार पटेल का रुख करते थे।

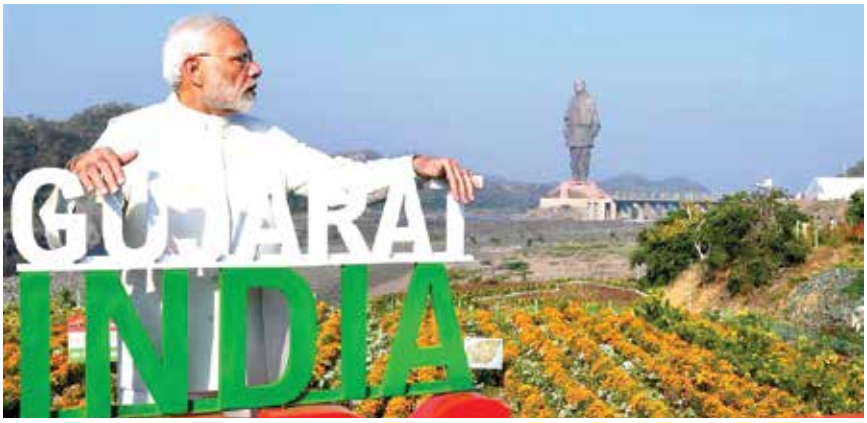

1947 में जब राजनीतिक समझौते के बारे में विचार-विमर्श अपने चरम पर था, तब सरोजिनी नायडू ने उन्हें 'संकल्प शक्ति वाले गतिशील व्यक्ति' की संज्ञा दी। उनके शब्दों और उनकी कार्य प्रणाली पर सभी को पूरा विश्वास था। जाति, धर्म, आयु से ऊपर उठकर सभी लोग सरदार पटेल का सम्मान करते थे। इस वर्ष सरदार की जयंती और अधिक विशेष है। 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से आज 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का उद्घाटन किया जा रहा है। नर्मदा के तट पर स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है।

धरती पुत्र सरदार पटेल हमारा सिर गर्व से ऊंचा करने के साथ हमें दृढ़ता प्रदान करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सरदार पटेल की इस विशाल प्रतिमा को हकीकत में बदलने के लिए दिन-रात काम किया। मैं 31 अक्टूबर 2013 के उस दिन को याद करता हूं, जब हमने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी थी। रिकॉर्ड समय में, इतनी बड़ी परियोजना तैयार हो गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को देखने आएं।

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' दिलों की एकता और हमारी मातृभूमि की भौगोलिक एकजुटता का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि आपस में बंटकर शायद हम डटकर मुकाबला नहीं कर पाएं। एकजुट रहकर, हम दुनिया का सामना कर सकते हैं और विकास तथा गौरव की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सरदार पटेल ने उपनिवेशवाद के इतिहास को ढहाने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया और राष्ट्रवाद की भावना के साथ एकता के भूगोल की रचना की।

उन्होंने भारत को छोटे क्षेत्रों अथवा राज्यों में विभाजित होने से बचाया और राष्ट्रीय ढांचे में सबसे कमजोर हिस्सों को जोड़ा। आज हम 130 करोड़ भारतीय नए भारत का निर्माण करने के लिए कंधे के कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, जो मजबूत, समृद्ध और समग्र होगा। प्रत्येक फैसला यह सुनिश्चित करके किया जा रहा है कि विकास का लाभ भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात के बिना समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचे जैसा कि सरदार पटेल चाहते थे। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)
(दैनिक भास्कर से साभार)

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' दिलों की एकता और हमारी मातृभूमि की भौगोलिक एकजुटता का प्रतीक है। यह याद दिलाती है कि आपस में बंटकर शायद हम डटकर मुकाबला नहीं कर पाएं। एकजुट रहकर, हम दुनिया का सामना कर सकते हैं और विकास तथा गौरव की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सरदार पटेल ने उपनिवेशवाद के इतिहास को ढहाने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया और राष्ट्रवाद की भावना के साथ एकता के भूगोल की रचना की।

भारत-जापान के बीच 75 अरब डॉलर की मुद्रा अदला-बदली पर समझौता

हाई स्पीड रेल परियोजना समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वार्षिक शिखर वार्ता के लिए 28-29 अक्टूबर को जापान की यात्रा की। प्रधानमंत्री के रूप में सितंबर, 2014 में जापान की अपनी पहली यात्रा के बाद से श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से यह 12वीं मुलाकात थी।

इस यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच 75 अरब डॉलर की मुद्रा अदला-बदली (करैंसी स्वैप) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते की मदद से विदेशी मुद्रा विनिमय के मामले में बड़ी राहत मिलेगी और यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और प्रगाढ़ करेगा। साथ ही, भारत और जापान ने एक हाई स्पीड रेल परियोजना और नौसेना सहयोग समेत छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये तथा टू प्लस टू वार्ता करने पर सहमति जतायी।

शिखर वार्ता में दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र के हालात समेत विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में विकास की समीक्षा की और सहयोग के नये क्षेत्रों पर भी बात की। उन्होंने भारत-प्रशांत में शांति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया, जहां चीन अपनी शक्ति दिखा रहा है। दोनों नेताओं ने सहमति जतायी कि भारत और जापान को एक व्यवस्था आधारित और समावेशी वैश्विक व्यवस्था के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों के बीच टू प्लस टू वार्ता करने पर सहमति जतायी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को प्रेस वक्तव्य में कहा कि जापान पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं का संगम है। यह वही महान देश है जिसने सिखाया है कि मानव जाति के विकास का रास्ता पुरातन और नूतन के बीच टकराव का नहीं, बल्कि उनके सह-अस्तित्व और सृजन का है। 'नये का स्वागत और पुराने का सम्मान', यह जापान की विश्व सभ्यता को प्रमुख देन है और साथ ही भारत और जापान की एक गहरी समानता भी।

श्री मोदी ने कहा कि जापान और भारत के सम्बन्धों को हिन्द और प्रशांत महासागरों सी गहराई और विस्तार प्राप्त हैं। ये सम्बन्ध लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रताओं के प्रति और रूल ऑफ़ लॉ के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बीच पूरी सहमति है कि हम अपने सहयोग को डिजिटल पार्टनरशिप से साइबर स्पेस तक, स्वास्थ्य से रक्षा-सुरक्षा तक और सागर से अंतरिक्ष तक, हर क्षेत्र में अबाध गति देंगे। मुझे

बताया गया है कि आज जापान के निवेशकों ने भारत में 2.5 बिलियन डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है। इससे भारत में लगभग 30 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय करेन्सी स्वाप व्यवस्था पर हुई सहमति में हमारा आपसी विश्वास और हमारी आर्थिक साझेदारी की निरन्तर बढ़ती हुई नज़दीकी साफ़ तौर पर झलकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन इसके रूप-स्वरुप पर प्रश्न हैं। किसका फायदा होगा, क्या करना होगा, ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन एक बात साफ है। भारत और जापान के सहयोग के बिना 21वीं सदी एशिया की सदी नहीं हो सकती। आबे सान और मैं हमारे विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल सोलर अलायन्स में जापान का प्रवेश विश्व के हित में ऐसे सहयोग का एक और उज्जवल उदाहरण बनेगा।

श्री मोदी ने कहा कि अगले वर्ष जापान ओसाका में G-20 समिट की मेज़बानी करेगा। अगले वर्ष रगबी वर्ल्ड कप भी जापान में आयोजित किया जायेगा। पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया में आयोजित होगा और फिर 2020 में ओलम्पिक्स का आयोजन टोक्यो में होगा। इन सभी महत्वपूर्ण वैश्विक इवेंट्स के लिए, मेरी ओर से और समस्त भारत की ओर से हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-जापान के संबंधों में प्रगति जापान की काईज़न दर्शन की तरह असीम है। प्रधानमंत्री आबे के साथ मिलकर इन संबंधों को और अधिक मज़बूत बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।

प्रधानमंत्री द्वारा टोक्यो में 'मेक इन इंडिया' सेमिनार का संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को टोक्यो में 'मेक इन इंडियाः अफ्रीका में भारत-जापान साझेदारी और डिजिटल भागीदारी' पर एक संगोष्ठी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि केन्द्र सरकार ने 'कारोबार में सुगमता बढ़ाने' के साथ-साथ 'देश के नागरिकों के लिए जीवन यापन में सहूलियत' सुनिश्चित करने पर किस तरह से अपना ध्यान केन्द्रित कर रखा है।

उन्होंने भारत में बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों की मौजूदगी पर

खुशी जताई। भारत में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में जापान के एक साझेदार होने की बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने पिछले चार वर्षों के दौरान आर्थिक मोर्चे पर भारत के शानदार प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया।

श्री मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए अन्य प्रमुख बदलावों का उल्लेख किया, जिनमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख होना, डिजिटल लेन-देन, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इत्यादि भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मध्यम वर्ग के बढ़ते आकार और विशाल युवा आबादी की बदौलत जापानी निवेशकों के लिए असंख्य नए अवसर सृजित हुए हैं। इस संदर्भ में उन्होंने किफायती विनिर्माण, आईटी उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों से आवाजाही (मोबिलिटी), इत्यादि सेक्टरों का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच साझा मूल्यों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही देश भारत-प्रशांत, दक्षिण एशिया और अफ्रीका सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में मजबूत विकास साझेदारियां विकसित किए जाने के बारे में आशान्वित हैं।

भारतीय समुदाय जापान में भारत के प्रतिनिधि हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया और पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किए जाने के लिए जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो आबे और जापान के लोगों का आभार जताया। श्री मोदी ने भारतीय समुदाय को जापान में भारत का प्रतिनिधि बताते हुए उनसे भारत में निवेश करने और अपनी मातृभूमि के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने का आग्रह किया।

पिछले चार वर्षों की अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लगातार वैश्विक अनुप्रयोगों की भावना के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन का भारत का मॉडल, खासकर,जन धन योजना, मोबाइल, आधार, ट्रिनिटी और डिजिटल लेनदेन मॉडल की आज पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है।

श्री मोदी ने इस अवसर पर भारत के बेहद सफल अंतरिक्ष कार्यक्रमों और मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए आज भारत, दुनिया में इलेक्ट्रानिक और ऑटोमोबाइल विनिमार्ण के बड़े केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

प्रधानमंत्री ने न्यू इंडिया के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में जापान से मिल रहे सहयोग का उल्लेख करते हुए भारतीय समुदाय से भारत और जापान के बीच संबंधों को लगातार सुधारने के लिए प्रयासरत रहने का आग्रह किया। ■

भारत में व्यापार करना हुआ सुगम

अरुण जेटली

विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में आगामी वर्ष के लिए 'व्यवसाय की सुगमता' पर अपनी रैंकिंग जारी करता है। यह रैंकिंग किसी भी देश में व्यापार करने के लिए मिलने वाले माहौल पर आधारित होता है और इसका विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 मई की तिथि को निर्धारित किया गया है। इस रैंकिंग को विश्व बैंक के स्वतंत्र शोध के तौर पर देखा जाता है और इसके लिए तय 10 मानकों के आधार पर ग्रेड दिए जाते है। इस आकलन में सामान्यताओं के लिए कोई जगह नहीं है। इन सुधारों को विशिष्ट होना चाहिए और अपने विशिष्ट प्रयासों की बदौलत भारत अब इस रैंकिंग में 190 देशों की सूची में 77वें स्थान पर पहुंच गया है।

यूपीए सरकार के दौरान भारत की स्थिति

यूपीए सरकार के दस वर्षों के शासनकाल के दौरान देश ने भ्रष्टाचार के सभी रिकार्डों को टूटते हुए देखा। वहीं देश नीति पक्षाघात और कांग्रेस की गैर सुधारवादी नीतियों से भी जूझता रहा। यही कारण है कि यूपीए-2 के पांच सालों के कार्यकाल में भारत वैश्विक रैंकिंग में 134, 132, 132, 134 और आखिरकार 142 स्थान पर लुढ़क गया। यह यूपीए सरकार की बड़ी नाकामयाबी थी। इस दौरान भारत के साथ व्यापार करना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाने लगा था। निवेशक भारत आने में सावधानी बरत रहे थे। इसके विपरीत मौजूदा निवेशक भारत को छोड़ने का मन बना रहे थे और कुछ छोड़ भी चुके थे।

एनडीए सरकार का प्रदर्शन

साल 2014 में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर कहा था कि हमारी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत 'व्यवसाय करने में सुगमता' इस रैंकिंग में पहले पचास देशों में अपनी जगह बनाए। उनकी यह घोषणा एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस रैंकिंग में 92 स्थानों की छलांग लगानी थी। वहीं, इस रैंकिंग में शामिल शीर्ष देशों के साथ प्रतिस्पर्धा बेहद ही कठिन साबित होने वाली थी, जिसके लिए निर्धारित दस श्रेणियों में सुधार करने की आवश्यकता थी और यह प्रतिस्पर्धा जब और कठिन होने वाली थी जब यह देश निरंतर अपने देश में विशिष्ट परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन परिवर्तनों के लिए कानून, विनियमन, नीति निर्णय और प्रशासनिक सुधारों में बदलाव की आवश्यकता होती है। वहीं, तकनीकी नवाचारों को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस रैंकिंग में 92 स्थानों की छलांग लगाना एक कठिन काम है। हमारे इस लक्ष्य को लेकर देश में बहुत से लोग आशावादी नहीं थे और उन्होंने इसे एक अविश्वसनीय लक्ष्य के रूप में लिया।

हमारी सरकार ने साल 2014 से इस रैंकिंग के प्रत्येक मानदंडों पर काम करना शुरू किया। इसके लिए केवल परिवर्तन की घोषणा या कोई कानून या नीति निर्धारण कर देना पर्याप्त नहीं था, बल्कि इसका असर जमीन पर दिखाई देना बेहद जरूरी था। विश्व बैंक केवल घोषणाओं को सुधार के रूप में नहीं मान्यता देता है। इन सुधारों को एक समयबद्ध सीमा के अंदर करना बेहद जरूरी था।

वहीं, विरासत में हमें मिली 142वीं रैंकिंग के साथ हम आगे बढ़े, पहले दो वर्षों में हमारी रैंकिंग में कुछ सुधार देखा गया और हम 130वें स्थान पर आने में कामयाब रहे। वहीं, तीसरे वर्ष में, हमने 30 पदों की एक लंबी छलांग लगाई और 100वें स्थान पर जा पहुंचे। ऐसे ही चौथे वर्ष में, हम 77वें स्थान पर आसीन होने में कामयाब हुए। तो कुल मिलाकर इन चार वर्षों के दौरान भारत इस रैंकिंग में 65 स्थानों की छलांग के साथ आज 77वें स्थान पर आसीन है। हमारा लक्ष्य अभी भी 27 स्थान दूर हैं, पर पहले असंभव माने जाने वाला लक्ष्य अब सभी को संभव लग रहा है।

यूपीए सरकार के दस वर्षों के शासनकाल के दौरान देश ने भ्रष्टाचार के सभी रिकार्डों को टूटते हुए देखा। वहीं देश नीति पक्षाघात और कांग्रेस की गैर सुधारवादी नीतियों से भी जूझता रहा। यही कारण है कि यूपीए-2 के पांच सालों के कार्यकाल में भारत वैश्विक रैंकिंग में 134, 132, 132, 134 और आखिरकार 142 स्थान पर लुढ़क गया। यह यूपीए सरकार की बड़ी नाकामयाबी थी।

सुधारों की स्थिति

'व्यापार शुरू करने' की श्रेणी में हमने पिछले चार वर्षों में 21 अंकों का सुधार देखा है। 'निर्माण गतिविधि' में चार साल में 132 अंक का भारी सुधार हुआ है। निर्माण संबंधित अनुमति पत्र अब ऑनलाइन हासिल किए जा सकते है, जिसके लिए एक समय सीमा का निर्धारण भी किया गया है। अगर उस समय के भीतर यह अनुमति पत्र प्राप्त नहीं होता हैं, तो उसे स्वीकृति के तौर ही देखा जाता है।

'बिजली प्राप्त करने' की श्रेणी में हमने एक असाधारण 132 पदों की छलांग लगाई है। संपत्ति पंजीकरण के मामले में हम अभी भी 166 स्थान पर बने हुए हैं। 'क्रेडिट प्राप्त करने' की श्रेणी में हम 22वें स्थान पर हैं। 'अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा' की श्रेणी में हम 7वें स्थान पर हैं, जो किसी भी श्रेणी में हमारी सर्वोच्च स्थिति है। 'सीमा पार व्यापार' श्रेणी में हम 146 वें स्थान से बढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

जीएसटी और दिवालियापन संबन्धित कानून के लागू होने के बाद हमने 'करों का भुगतान' श्रेणी में 37 स्थानों का सुधार देखा है, लेकिन अभी भी हम 121वें स्थान पर हैं। 'दिवालियापन को हल करने' संबन्धित श्रेणी में हमने 29 पदों का सुधार किया है, लेकिन अभी भी हम 108वें स्थान पर हैं। 'अनुबंधों के प्रवर्तन' श्रेणी में हमने 23 स्थानों को सुधार किया है और हम 163वें स्थान पर हैं।

आगे की राह

मौजूदा व्यवस्था में 'करों का भुगतान' और 'दिवालियापन' के मामलों से निबटने के लिए जीएसटी और एनसीएलटी तंत्र मौजूद हैं। इनके शुरुआती परिणाम काफी उत्साहजनक हैं और जब इस पूरे वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन आकलन होगों, तो यह मानना तार्किक है कि हम इन दो श्रेणियों में ठोस रूप से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार 'अनुबंधों के प्रवर्तन' के संबंधित मामलों से प्रभावी तौर से निबटने के लिए 'स्पेसिफिक रेलीफ़ एक्ट' (विशिष्ट राहत अधिनियम) में संशोधन किया गया है। देश के विभिन्न जिलों में वाणिज्यिक अदालतें स्थापित की गई हैं। न्यायिक हस्तक्षेप को कम करने के और इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यस्थता अधिनियम में भी संशोधन किया गया है।

इसके अतिरिक्त 'व्यवसाय शुरू करने' से संबंधित नियमों को सुगम बनाने के लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है। पिछले चार वर्षों में हमारी रैंकिंग में 21 स्थानों को इजाफा हुआ है और आज हम 137वें स्थान पर बने हुए हैं। हालांकि इसे संतोषजनक स्थिति नहीं कही जा सकती है। अभी केंद्र और राज्यों के स्तर पर बहुत से सुधारों की गुंजाइश बनी हुई है।

इन मानदंडों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि व्यावसायिक गतिविधि में लगने वाली समय अवधि को कम किया जाए। लागत में कमी और विभिन्न प्रक्रियाओं की संख्या को कम करने पर जोर दिया जाए। यह कोई असंभव कार्य नहीं है। यदि हम वर्तमान गति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर पाएगें। एक लक्ष्य केंद्रित और उद्देश्य उन्मुख सरकार ही इसे हासिल कर सकती थी। ■

(लेखक केंद्रीय वित मंत्री हैं)

हिंदू परंपराओं को बचाने के लिए केरल में आक्रोश

एम. राजशेखर पानिकर

सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर, 2018 के फैसले ने सभी उम्र की महिलाओं को केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी है।

सबरीमाला एकमात्र मंदिर है जहां पांच करोड़ से अधिक भक्त दो महीने की सालाना तीर्थयात्रा के दौरान पहुंचते हैं। मंदिर के देवता भगवान अयप्पा को 'नाइष्टिका ब्रह्मचारी' (बारहमासी अविवाहित) माना जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत से संबंधित सालों पुरानी मान्यता और रीति-रिवाज के मद्देनजर 10 से 50 वर्षों के बीच की महिलाओं का प्रवेश मंदिर में वर्जित माना जाता है। इस परंपरा का लिंग भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। केरल में सैकड़ों अन्य अयप्पा मंदिर भी है, जहां सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं है। इस मंदिर में पूजा के दौरान भक्त रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, 41-दिन की तपस्या करते हैं, और 'इरुमुद्दीकेटु' लेते हैं (जहां एक नारियल अयप्पा भगवान के अभिषेक के लिए घी से भरा होता है, वहीं अन्य में चावल और दूसरे प्रसाद होते है)।

अयप्पा भक्तों को अयप्पा के रूप में ही देखा जाता है। यह एक दूसरे को 'स्वामी' शब्द से संबोधित करते है, जिसका अर्थ होता है 'भगवान'। जो लोग इस तपस्या को करते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण मिलता है। वहीं मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लिखा है, 'ततत्वंअसि' ("tat tvam asi"- "आप वह हैं"- "आप भगवान हैं")।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदुओं को लगता है कि उनको अपने ही मंदिर में एक विशेष पूजा करने से वंचित किया जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकार के समझौता करने जैसा है। सीपीएम के नेतृत्व वाली वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फैसले के विरोध में उठी अयप्पा भक्तों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया है। यह मंदिर, जहां केरल राज्य की आबादी से लगभग दोगुनी संख्या में हिंदू तीर्थयात्री आते हैं, हमेशा से ही मार्क्सवादियों और तथाकथित सैद्धांतिक धार्मिक समूहों की नजरों में खटकता रहा है। यह मंदिर हमेशा ही मार्क्सवादी भौतिकवादी विचारधारा और धर्मांतरण के खिलाफ एक किले के रूप में खड़ा रहा है। 1957 में, कुछ अराजकवादी तत्वों ने मंदिर परिसर को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन को स्थापित किया गया था। इस दौरान हिंदुओं के क्रोध और पीड़ा का लाभ उठाकर पहली बार मार्क्सवादी सरकार सत्ता में आई। उन्होंने वादा किया कि सत्ता में आने पर वह कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित करने और अपराधियों को दंडित के लिए वचनबद्ध है, लेकिन जब वे सत्ता में आए, तो उन्होंने राज्य के प्रभावशाली धर्मांतरण करने वाले समूहों की प्रतिक्रिया के डर से इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में राज्य की पुलिस ने 17 अक्टूबर को पांच दिवसीय पवित्र पूजा के दौरान मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन, सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्यों और पूर्व राज्य सचिव के आदेश पर कुछ ढोंगी महिलाओं को भक्तों के रूप प्रवेश करवाने का प्रयास किया। वहां मौजूद भक्त इस घटना को देखकर चौंक गए, पुलिस के साथ मंदिर जाने के लिए पहुंची यह वहीं महिला कार्यकर्ता थी जो पूर्व में 'किस ऑफ लव', 'मंगलसूत्र ब्रेकिंग' जैसे अभियानों का हिस्सा रह चुकी थी। पुलिस ने न केवल इन महिला को सुरक्षा प्रदान की, बल्कि लोगों की नजर में आने से बचाने के लिए पुलिस की वर्दी पहनाकर इन महिला कार्यकर्ता को अपने साथ लाई थी।

लेकिन हजारों श्रद्धालु 'शरणम् अयप्पा' का जप करते हुए एक मजबूत दीवार के रूप में पुलिस द्वारा समर्थित सरकारी मशीनरी और इन नास्तिक महिलाओं के सामने खड़े रहे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान पुलिस का संरक्षण प्राप्त इन महिला कार्यकर्ताओं ने कई अवसरों पर अयप्पा भक्तों को अपनी उत्तेजनापूर्ण फब्तियों से उकसाने का काम किया, लेकिन इन भक्तों ने लगातार अत्यधिक संयम बनाए रखा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अयप्पा भक्तों पर पुलिस ने बड़ी ही क्रूरता से डंडे बरसाए और इस दौरान हजारों वाहन को नुकसान पहुंचा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान तकरीबन 3500 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इस संदर्भ में 500 से अधिक मामले भी पुलिस ने दर्ज किए।

इन अयप्पा भक्तों को गिरफ्तार करने के लिए रात का समय चुना गया और उन्हें हत्यारों एवं डकैतों की तरह हाथ बांधकर ले जाया गया। इस मंजर ने वह मौजूद लोगों के जहन में आपातकाल की उस कुख्यात आधी रात को फिर से ताजा कर दिया, जिसमें ऐसे ही हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की बर्बरता के बाद से गायब साठ वर्षीय अयप्पा भक्त शिवदास का क्षय शरीर सबरी जंगल में मिला, जो सत्तावादी शासन के खिलाफ मौजूदा संघर्ष का पहला शहीद बन गया है। वहीं, सरकार भी कथित तौर पर जन भावनाओं के इतर अदालत के आदेश को

मजबूती से लागू करने में लगी है। मुख्यमंत्री के व्यवहार की तुलना हिटलर या स्टालिन से की जा सकती है जो शांतिपूर्ण आंदोलन के दमन के लिए हर पैतरा अपना रहे हैं। वह स्थानीय सीपीएम कैडर के स्तर पर जाकर व्यवहार कर रहे है और यह भूल गए है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

जल्दबाजी में सबरीमाला के फैसले को लागू करने में लगी पिनारायी विजयन की सरकार का रवैया उनकी पार्टी के अत्यधिक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को जाहिर करता है। ऐसे भी कई मामले हैं, जिनकों लेकर सरकार ने अदालती आदेश के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की है।

चूंकि सरकार इस संघर्ष के पहले दौर में कामयाब नहीं हुई, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री का पूरा प्रयास है कि अगामी दिनों में वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। इस रिपोर्ट को फाइल करने के दौरान यह बात हमारे संज्ञान में आई है कि 12 सीपीएम समर्थित महिलाओं ने सबरीमाला में जाने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी है।

वही मुख्यमंत्री पिनारायी भी इन महिलाओं को पूरा सहयोग देने का मन बना चुके है। सबरीमाला मंदिर एक दिन के लिए नवंबर 5 को 'चिथिरा अटविशेषम' के अवसर में फिर खुलेगा। इस दिन त्रावणकोर शाही परिवार के मुखिया चिथिरा थिरुनल बलराम वर्मा की जयंती का जश्न मनाया जाता है। मुख्यमंत्री की सनक को पूरा करने के लिए पार्टी गांव—गांव से अपने कैडरों को संगठित कर रही है, ताकि इन महिलाओं को संरक्षण देने के लिए कैडर के लोगों और पुलिसकर्मियों का उपयोग किया जा सकें।

अयप्पा भक्तों ने भी यह निश्चिय कर लिया है कि ऐसा केवल उनकी लाश गिरने के बाद ही होगा। इसी मुद्दे पर कोट्टायम में हिंदूवादी संगठनों की एक बैठक हुई, जिसमें 120 हिंदू संगठनों ने सीपीएम की अगुवाई वाली सरकार के मंसूबों को नाकामयाब बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई, ताकि मंदिर की पवित्रता और युग से चले आ रहे रीति-रिवाजों को नष्ट होने से बचाया जा सके।

पूरे केरल राज्य में इस मुद्दे को लेकर विरोध—प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठकों और अयप्पा शरण मंत्र की गूंज को स्पष्ट देखा जा सकता है। लाखों श्रद्धालुओं, जिसमें विशेष तौर से महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है स्वेच्छा से सड़कों आ गयी है।

मुख्यमंत्री शांतिपूर्ण आन्दोलनकारियों पर असामाजिक तत्व होने का आरोप लगा रहे है, जो कम्युनिस्ट आंदोलन द्वारा लादे गए सभी प्रगतिशील कदमों के भ्रम को तोड़ का काम कर रहे है। इतिहास भी गवाह है कि जब भी कोई सामाजिक आंदोलन हुआ है तो उसकी अगवानी नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामी और अयंकली जैसे समाज सुधारकों ने की है और फिर चाहें मंदिरों में प्रवेश का मुद्दा हो, सड़कों पर चलने का अधिकार, अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन हो। यह सभी आंदोलन कम्युनिस्ट आंदोलन के आगमन से बहुत पहले ही राज्य में हो चुके है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 27 अक्टूबर को स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी अयप्पा भक्तों के साथ खड़ी है। "आज केरल में, धार्मिक मान्यताओं और राज्य सरकार की क्रूरता के बीच एक संघर्ष चल रहा है। भाजपा, आरएसएस और अन्य संगठनों के 2,000 से अधिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह ने कहा, हमारी पार्टी भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान अयप्पा के भक्तों के आंदोलन को दबाने के लिए केरल सरकार के प्रयासों "आग के साथ खेलना" जैसे है। अमित शाह ने पार्टी के कन्नूर जिला मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान यह बात कही।

शाह ने राज्य सरकार पर सबरीमाला मंदिर और "हिंदू परंपराओं" को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीपीआई (एम) सरकार को हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देगी। राज्य में "महिलाओं के लिए किसी अन्य अयप्पा मंदिर में प्रार्थना करने पर कोई पाबंदी नहीं है। शाह ने कहा कि सबरीमाला मंदिर की विशिष्टता को संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिंदू मंदिरों के खिलाफ "षड्यंत्र" कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में आपातकाल जैसी हालात पैदा हो गए है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर पर अदालत के आदेश का पालन भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विजयादशमी के भाषण में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने से पहले भक्तों की भावनाओं पर भी विचार करना चाहिए था।

अब मार्क्सवादी एक नयी रणनीति

पर काम कर रहे है। सबसे पहले वे यह दिखाना चाहते हैं कि वह लिंग समानता के सबसे बड़े हिमायती है। दूसरा, पिनारायी यह साबित करना चाहता है कि वह संघ परिवार के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए है, जो पूरी तरह से भक्तों के शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता है। वह अपने इस प्रयास से संघ परिवार का विरोध करने वाली सभी ताकत को एकजुट करना चाहते हैं, जिससे वह वामपंथ के अंतिम किले को बचा सके।

गौरतलब है कि मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की मांग किसी भक्त के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि यंग एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा इस मांग को उठाया गया था। जब मामला अदालत में आया, तो राज्य सरकार को इस मामले में कोई राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं दिया और राज्य नियंत्रित मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं किया, जो करोड़ों भक्तों के साथ धोखा करने जैसा था। दुर्भाग्यवश, इस मामले में, अभियोगी और आरोपी के हितों फैसला आते आते एक समान हो गए थे। इसलिए इस मामले में जब निर्णय आया तो दोनों ही पक्षों ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह फैसले एक चर्चित तीर्थ केंद्र को नष्ट करने के पक्ष में था। वैसे भी उनका प्रसिद्ध उद्धरण है "जब एक पूजा स्थान नष्ट होता है, तो बहुत सारे अंधविश्वास भी खत्म हो जाते है"।

रिपोर्टों के मुताबिक इस फैसले के खिलाफ लगभग 40 पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं और यदि 13 नवंबर को पुनर्विचार याचिकाओं पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया, तो 16 नवंबर से दो महीने लंबे तीर्थयात्रा के मौसम में एकत्र होने वाले लाखों भक्तों के बीच सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना एक चुनौती होगी।

"सीपीएम सरकार मंदिर को नष्ट करने की कोशिश कर रही है, जो हिंदूवादी सुधारों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह सबरीमाला मंदिर के खिलाफ एक कम्युनिस्ट षड्यंत्र है", भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पी एस श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि राज्य सरकार मंदिर की परंपराओं को बचाने के लिए एक अध्यादेश शीघ्र पारित करे।

प्रदेश की भापजा इकाई और उसके सहयोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए राज्य सरकार और देवस्वाम बोर्ड को मजबूर करने के लिए सबरीमाला संचार यात्रा का आह्वान किया है। यात्रा पांडलम में अयप्पा के जन्मस्थान से शुरू हो कर तिरुवनंतपुरम तक पहुंचेगी, जिसमें लाखों अयप्पा भक्तों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की मांग किसी भक्त के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि यंग एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा इस मांग को उठाया गया था। जब मामला अदालत में आया, तो राज्य सरकार को इस मामले में कोई राजनीतिक लाभ दिखाई नहीं दिया और राज्य नियंत्रित मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वाम बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को प्रभावी रूप से प्रस्तुत नहीं किया, जो करोड़ों भक्तों के साथ धोखा करने जैसा था।

एनडीए ने अयप्पा भक्तों की गिरफ्तारी और राज्य सरकार के कठोर कदमों के खिलाफ शांतिपूर्ण उपवास आयोजन करने का आह्वान भी किया है। "कम्युनिस्ट पार्टी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बहाने सबरीमाला को युद्ध के मैदान में बदलना चाहती है। यह काम नहीं करेगा। बीजेपी इसका कड़ा विरोध करेगी। यात्रा का नेतृत्व कर रहे श्रीधरन पिल्लई ने कहा कि सरकार के संरक्षण में ढोंगी महिलाओं का मंदिर परिसर में प्रवेश अयप्पा भक्तों को उकसाने का काम कर रहा है। बीडीजेएस के प्रदेश अध्यक्ष थूशर वेल्लप्पाल्ली ने कहा, "इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट रहना चाहिए।"

इस मामले में उम्मीद की जा रही थी कि देवस्वाम बोर्ड भक्तों के पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन सीपीएम और एलडीएफ सरकार की शह पर वह पांडलम रॉयल परिवार, सबरीमाला तांत्री और भक्तों के विरोध में खड़ा दिखाई देता है और उनको चुनौती दे रहा है। भाजपा के महासचिव एमटी रमेश ने कहा, भाजपा भक्तों के साथ खड़ी है।

"कुछ महीनों पहले जब पुलिस ने मुन्नार के पप्पथिचोला में अतिक्रमणियों द्वारा एक बड़े कंक्रीट क्रॉस को हटाने की कार्रवाई की थी, तो पिनारायी ने कहा था कि 'सरकारी आदेश का पालन करते वक्त जन भावनाओं को प्रभावित किए बिना कार्रवाई किए जाने का प्रयास करना चाहिए। रमेश ने पूछा, "जब सबरीमाला की बात आती है तो सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है।"

पिनारायी ने इतिहास से सबक नहीं लिया है। इससे पहले दो अवसरों पर राजनेताओं को भक्तों की ताकत के आगे झुकना पड़ा था। पहला मामला मलप्पुरम में थाली मंदिर का था, जहां तत्कालीन कम्युनिस्ट के मुख्यमंत्री ई.एम.एस. नंबूदरिपाद ने पूर्व मैसूर शासक टिपू द्वारा बर्बाद मंदिर के नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी थी। स्वतंत्रता सेनानी के. केलप्पन के नेतृत्व में इसके विरोध में निरंतर संघर्ष हुआ और अंतः थाली में एक शानदार मंदिर बनाने में सफलता प्राप्त हुई। वहीं के. करुणाकरन के शासनकाल के दौरान कुछ ईसाइ समूहों ने 18 हिल श्रृंखला में मौजूद सबरीमाला बाग में क्रॉस लगाने का प्रयास किया। जिसके विरोध में वर्तमान मिजोरम गवर्नर कुमानमान राजशेखरन के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात उन्हें हिंदू तीर्थयात्रा क्षेत्र से बाहर होने पर मजबूर होना पड़ा।

सबरीमाला मुद्दे ने कांग्रेस के नेतृत्व

में चल रहे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के दोहरे चरित्र को जनता के सामने ला दिया है। विपक्षी नेता रमेश चेनिथला ने सुझाव दिया कि मंदिर का रखरखाव करने वाले देवस्वाम बोर्ड को फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा, "इस आदेश ने भक्तों के बीच एक गंभीर चिंता को जन्म दिया है और सरकार को भी इस आदेश को लागू करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।" लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन मतों से अपनी राय कुछ अलग रखते हैं। उन्होंने सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश की हिमायत की है। इसके माध्यम से कांग्रेस दोनों पक्षों की हिमायती बनाकर

सामने आना चाहती है, लेकिन भक्तों का मानना है कि पार्टी ने उन्हें बीच मंझधार में छोड़ दिया है।

सीपीएम द्वारा मनोनित देवस्वाम बोर्ड के अध्यक्ष ए. पद्मकुमार मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के दबाव में पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया।

पांडलम रॉयल परिवार के सदस्य आरआर वर्मा ने कहा, "सबरीमाला पांडलम शाही परिवार का मंदिर था। हमने इसे सरकार को सौंप दिया। अदालत ने स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया है। इस फैसले से भक्तों का अपमान हुआ है।"

अयप्पा के भक्तों में से एक अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि लंबे समय से पालन होने वाली मंदिर की परंपराओं में कोई "हस्तक्षेप" नहीं होना चाहिए। "जब आप एक मंदिर के बारे में बात करते हैं, तो हर मंदिर की अपनी परंपराएं और अनुष्ठान होते हैं। मेरी विनम्र राय यह है कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अभिनेता ने कहा कि धर्म और संबंधित अनुष्ठानों के मामले में सावधानी बरती जानी चाहिए।

यह सीपीएम और उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा हर हिंदू धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ विवाद फैलाने की श्रृंखला की एक और कड़ी है। हिंदू देवी—देवता, माथे पर चंदन या कुमकुम लगाना, मंदिर में पूजा, पारिवारिक बंधन, भारतीय संस्कृति यह सभी उनके उपहास का विषय रहे हैं। केवल वे लोग जो अराजकता और भारत-विरोधी विचार रखते है या लिखते हैं, उन्हें ही संरक्षण दिया जाता है। इस मामले में भी सरकार ने बड़ी ही चतुराई से इस तथ्य को छुपाया कि लाखों महिला भक्त हर साल सबरीमाला में दर्शन के लिए आते हैं और यहां लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

अब, मार्क्सवादी पूजा की एक अनोखी जगह चाहते हैं जहां भक्त स्थान की विशिष्टता के लिए वहां नहीं आते हो, केवल एक झुंड के तौर पर उस स्थान पर जाए। मार्क्सवादियों को भी एहसास है कि जब तक इस स्थान में भक्तों का विश्वास दृढ़ रहेगा, तब तक उनकी भौतिक विचारधारा के अस्तित्व के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए वे इस केंद्र को निशाना बना रहे हैं।

इस मामले में कांग्रेस को पहले झटका तब लगा जब केपीसीसी कार्यकारी समिति के सदस्य और पूर्व देवस्वाम बोर्ड के अध्यक्ष जी. रमन नायर ने पांडलम में एनडीए के सबरीमाला संरक्षण मार्च का उद्घाटन किया और बाद में पार्टी से उनकों निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने चार अन्य दिग्गजों के साथ भाजपा में शामिल होने का निर्णय किया, जिसमें पूर्व इसरो के अध्यक्ष जी. माधवन नायर भी शामिल थे। अमित शाह की उपस्थिति इन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया।

मंदिर मुद्दा पिनारायी विजयन के लिए आत्मघाती साबित होगा। यदि वह अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ते है, तो परंपरागत हिंदू मतदाता जो अब तक सीपीएम के साथ खड़े थे, पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। पिनारायी सोच रहे है कि हिंदू वोटों की भरपाई वह एसडीपीआई, लोकप्रिय मोर्चा और ईसाई वोट के ध्रुवीकरण के माध्यम से पूरी कर लेंगे, लेकिन यह उनका एक सपना ही है। हजारों सीपीएम कार्यकर्ता पार्टी की गुटबाजी के चलते मंदिर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं।

जब तक केरल के मुख्यमंत्री एक राजनेता की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तब तक सैकड़ों सालों की कड़ी मेहनत से अर्जित राज्य के सभी सांस्कृतिक मूल्यों के एक झटके में खत्म होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक बार ऐसा होने के बाद, इस महान परंपरा का पुनर्निर्माण बहुत कठिन कार्य होगा। ■

(लेखक केरल भाजपा पत्रिका 'थिति' के संपादक हैं)

छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार चौथी बार भी भारी जीत दर्ज करेगी: डॉ. अनिल जैन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ और हरियाणा के प्रभारी डॉ. अनिल जैन को पूर्ण विश्वास है कि भाजपा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में 65 या उससे अधिक सीटों पर कब्जा कर भारी जीत दर्ज करेगी और चौथी बार राज्य में अपनी सरकार बनायेगी। कमल संदेश के सह संपादक राम प्रसाद त्रिपाठी और भाजपा मीडिया सेल, छत्तीसगढ़ के सदस्य हेमंत पनग्राही के साथ बातचीत में श्री जैन ने कहा कि कांग्रेस का झूठ जनता के सामने आ चुका है और इसलिए कांग्रेस हमारे लिए राज्य में कहीं भी चुनौती पेश नहीं कर रही है। प्रस्तुत है इस बातचीत के मुख्य अंशः—

छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए प्रयास कर रही है। पार्टी की चुनावी रणनीति पर प्रकाश डालें?

देखिए, पिछले 15 वर्षों में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए उल्लेखनीय काम किए हैं। यदि आप साल 2003 से पहले और अब राज्य में हुए विकास कार्य की तुलना करते हैं, तो आप इसमें जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। भाजपा की विकासशील नीतियों का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने डेढ़ दशक के शासनकाल के दौरान सफलतापूर्वक समाज के अंतिम व्यक्ति को अपनी विकास यात्रा से जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे ही साल 2014 के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी और इसका पूरा लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिला। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य के त्वरित विकास के लिए अपना सहयोग लगातार दे रही है। इसलिए हम आशावादी हैं कि इस बार हमारी पार्टी 90 सीटों में से 65 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार चौथी बार राज्य में अपनी सरकार बनायेगी।

आगामी विधानसभा चुनावों में किन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी?

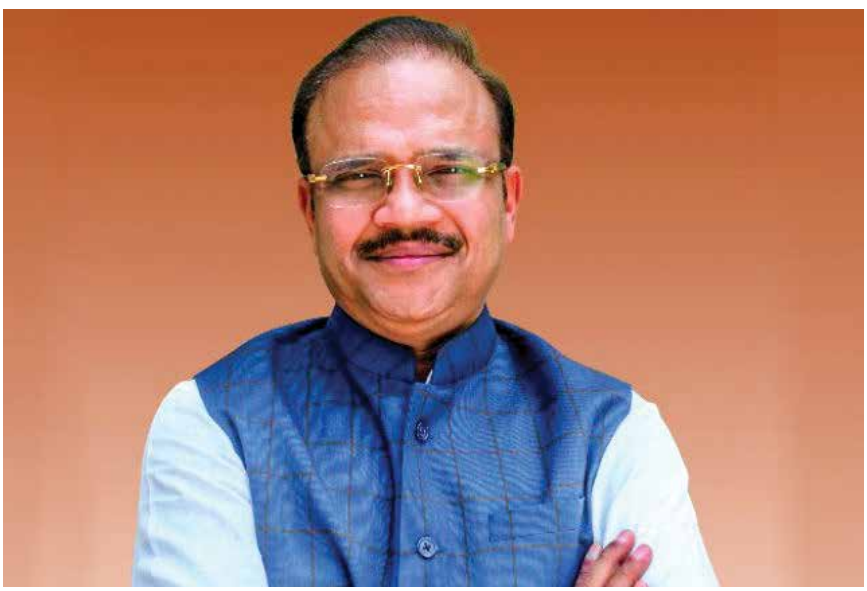

पार्टी के लिए आगामी चुनावों में राज्य के विकास का मुद्दा ही सबसे अहम होगा। विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को मिलने वाला चावल, नमक और चना पहले ही इस सरकार को विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दिला चुका है। राज्य में डर मुक्त और भूख मुक्त माहौल का निर्माण हुआ है। वहीं दूरसंचार क्रांति, तेंदुपत्ता इकठ्ठा करने वाले मजदूरों को बोनस, चरण पादुका और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं ने भी आम जनता को लाभान्वित किया हैं। पार्टी राज्य सरकार की इन उपलब्धियों को भी जनता के बीच लेकर जाएगी।

राज्य में कांग्रेस पार्टी की चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं?

राज्य में कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा बन गई है। जनता के समक्ष उसका झूठ कई मौकों पर उजागर हो चुका है। सीडी कांड से लेकर नक्सल समस्याओं पर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से केवल झूठ ही बोल रही है। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस पार्टी एकदम निचले स्तर पर चली गई है और ओछी राजनीति कर रही है। इसी का परिणाम है कि जनता कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस हमारे लिए राज्य में कहीं भी एक चुनौती के तौर पर खड़ी

दिखाई नहीं देती है।

विधानसभा चुनावों के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होंगे। क्या आपको लगता है कि भाजपा एक बार फिर राज्य में 2014 की उपलब्धि दोहराएगी?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है। देश लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा 300 सीटें हासिल करने में हमारी पार्टी कामयाब होगी और एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ देश की समृद्धि के लिए काम करेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है। देश लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब होगी। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी भाजपा 300 सीटें हासिल करने में हमारी पार्टी कामयाब होगी और एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ देश की समृद्धि के लिए काम करेगी।

छत्तीसगढ़ के अलावा आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं। हाल ही में हरियाणा में भाजपा सरकार ने चार साल पूरे किए हैं। हरियाणा में आप भाजपा सरकार की उपलब्धियों को कैसे देखते हैं?

श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा सरकार से पहले राज्य में भ्रष्टाचार का शासन हुआ करता था, लेकिन वहीं जब हम सत्ता में आए तो यह प्राथमिकता बदली और हमने राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य करना शुरू कर दिया। हमारी सरकार ने महिलाओं, खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों और अन्य लोगों के लिए कई कल्याण कदम उठाए, जिनकी प्रशंसा समाज के सभी वर्गों ने की। इन सभी सुधारों के चलते आज हरियाणा राज्य अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।

भाजपा की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और अगले साल होने वाले आम चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की जो बयार देश में बह रही है उससे देश का कोई भी कोना अछूता नहीं है। हरियाणा राज्य भी विकास की इस तेज गति का अनुभव कर रहा है। केंद्र सरकार ने मजबूत अर्थव्यवस्था, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक, आयुषमान भारत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सस्ते घर और सभी को बिजली आदि मुद्दों पर जोर दिया है। वही हरियाणा सरकार के विकास कार्यों के साथ-साथ राज्य की धारा को बदल दिया है। निश्चित तौर पर आगामी आम चुनाव इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निस्संदेह, लोकसभा और अगले विधानसभा चुनावों में भाजपा हरियाणा में भारी जीत दर्ज करेगी। ■

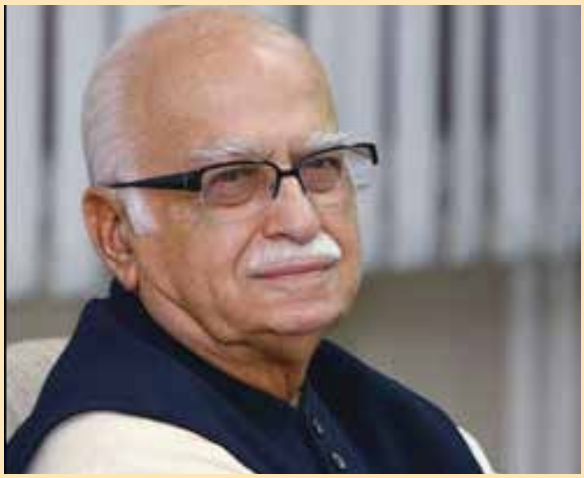

जीवेम शरदः शतम्!

जन्म : 08 नवम्बर

कमल सन्देश परिवार की ओर से भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनायें!

'भाजपा का मानना है विकास ही सभी समस्याओं का समाधान'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंबागढ़ चौकी, (खुज्जी विधानसभा, जिला राजनंदगांव), अतरिया (खैरागढ़ विधानसभा, जिला राजनंदगांव) और कोंडागांव (जिला कोंडागांव) में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता से एक बार फिर 'नवा छत्तीसगढ़' बनाने के लिए श्री रमण सिंह के नेतृत्व में दो-तिहाई से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की अपील की।

श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार फिर से

राज्य में विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने कहा कि एक ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका न कोई नेता है, न नीति है, न विकास करने की नीयत है और न ही कोई सिद्धांत है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका मानना है कि विकास ही सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने राज्य की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आप छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार बनाइये जो छत्तीसगढ़ को 'नवा छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़' बनाए और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय ही किया है। जब छत्तीगढ़ का यह हिस्सा मध्य प्रदेश में शामिल था, तब भी और जब यह राज्य बना तब भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लगातार अनदेखी करती रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने और तब के कांग्रेस के तमाम नेताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का विरोध किया। यह श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार थी, जिसने नए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब भी राज्य की जनता को विकास से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य की जनता का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को उखाड़ फेंकते हुए विकास की नई कहानी लिखने वाली भारतीय जनता पार्टी की श्री रमण सिंह सरकार का गठन करने का जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते पूरा परिदृश्य बदल गया और विकास समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सफल हो सका।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री रमण सिंह ने छत्तीसगढ़ में विकास को घर-घर पहुंचाने का महती कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में रेल, सड़क, बिजली, शौचालय, टीकाकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य - विकास के लगभग सभी पैमाने पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करने लगा है कि देश और प्रदेश का विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार आयेगी तो विकास डबल इंजन की गति से और आगे बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार आयेगी तो राज्य की महिलाओं को अपमानित करने के लिए सीडी बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि शर्म आती है ऐसी कांग्रेस पार्टी पर जो ऐसे नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है जो सीडी बनाकर राज्य की महिलाओं का अपमान करते हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल एक परिवार का विकास करने के अतिरिक्त देश में कहीं भी विकास नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने की मशीन बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का एक ही काम रह गया है - झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार-बार

बोलना और सार्वजनिक रूप से बोलना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस पार्टी की सोनिया-मनमोहन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को विकास के लिए महज 48,000 करोड़ रुपये की राशि दी, जबकि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर करने के लिए 1,37,927 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो यूपीए सरकार का लगभग तीन गुना है। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता को उनका अधिकार दिया है जिससे कांग्रेस ने उन्हें वंचित कर रखा था।

छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा कि रमण सिंह सरकार ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ की छवि को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार की विदाई के वक्त राज्य की विद्युत् उत्पादन क्षमता महज 4,000 मेगावाट थी, रमण सिंह सरकार ने इसे 22,000 मेगावाट तक पहुंचाने का काम किया है और 10,000 मेगावाट पर काम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत राज्य की 36 लाख से अधिक गरीब माताओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिली है। लगभग ढ़ाई लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं और गरीबों को दो वक्त का खाना देने के उद्देश्य से दो रुपये किलो चावल प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए अत्यंत ही गर्व हो रहा है कि श्री रमण सिंह ने चावल बांटने की योजना इतने अच्छे तरीके से और बिना किसी भ्रष्टाचार के इम्प्लीमेंट किया कि अब देश के कई राज्य इस प्रणाली को अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों एवं माताओं के पैरों में विनम्रता के साथ रमण सिंह सरकार ने चरण-पादुका पहनाने का काम किया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम हुए हैं और स्वास्थ्य के लिए भी विशेष प्रबंध किये गए हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के बजट को केवल 9,000 करोड़ रुपये वार्षिक पर छोड़ कर गई थी, जबकि श्री रमण सिंह सरकार के 15 सालों में यह बढ़कर 83,169 करोड़ रुपये हो गई है, लेकिन कांग्रेस को विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय भारतीय जनता पार्टी सरकार के 15 सालों में 13 हजार रुपये से बढ़कर 92 हजार करोड़ रुपये हो गई है।

नक्सलवाद पर एक कांग्रेस नेता के बयान की तीखी आलोचना करते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता नक्सलवाद को क्रांति की संज्ञा दे रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि नक्सलवाद इंसानियत का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के कारण छत्तीसगढ़ का विकास वर्षों तक बाधित रहा, लेकिन अपनी जान की परवाह किये बगैर श्री रमण सिंह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को नक्सलवाद में क्रांति दिखाई देती है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सीख देते हुए कहा कि राहुल गांधी, बम के धमाकों और गोलियों से कभी क्रांति नहीं आती, क्रांति तो तब आती है जब गरीबों को रहने के लिए घर मिलता है, गरीब माताओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिलती है। उनकी घरों में बिजली पहुंचती है, शौचालय पहुंचता है, बच्चों का टीकाकरण होता है और दो वक्त के खाने के लिए चावल मिलता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को क्रांति की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। उन्होंने सभा में उपस्थित जनता से पूछते हुए कहा कि राज्य से नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए या नहीं तो जनता ने एक स्वर में उद्घोष किया कि नक्सलवाद का जड़ से खात्मा होना ही चाहिए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी हाल ही में अर्बन माओवादी पकड़े गए तो कांग्रेस पार्टी इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताने लगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह मालूम होना चाहिए कि जवानों को मारना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, सड़कों को तोड़ना, पत्रकारों की हत्या करना, देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचना और बम धमाके करना कभी भी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया, जबकि रमण सिंह सरकार इसे ख़त्म कर राज्य में विकास की बयार लाना चाहती है।

छत्तीसगढ़ में रमण सिंह सरकार के 10 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार रही, जिसने लगातार राज्य के विकास में अवरोध उत्पन्न किया लेकिन पिछले पांच वर्षों से केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है। हमें 'नवा छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़' बनाना है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

श्री शाह ने कहा कि आजकल कांग्रेस नेता कहते घूम रहे हैं कि मेड इन जापान, मेड इन चाइना तो होता है, लेकिन मेड इन छत्तीसगढ़ क्यों नहीं होता? मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि पहले आप अपनी आंखों पर लगे इटैलियन चश्मे को तो उतारिये क्योंकि आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। आज छत्तीसगढ़ का सीमेंट, सरिया, एल्युमीनियम देश के विकास में योगदान दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ की बिजली दूसरे राज्यों में वितरित की जाती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमण सिंह सरकार के 10 वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार रही, जिसने लगातार राज्य के विकास में अवरोध उत्पन्न किया लेकिन पिछले पांच वर्षों से केंद्र में भी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास डबल इंजन की गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें 'नवा छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़' बनाना है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ■

लद्दाख के इतिहास से न्याय

अम्बा चरण वशिष्ठ

होने को तो जम्मू-कश्मीर राज्य के तीन संभाग हैं- जम्मू, कश्मीर व लद्दाख, पर जब समस्या की बात आती है तो नाम केवल कश्मीर का ही लिया जाता है। जम्मू-कश्मीर की बात हो तो लद्दाख को तो लगभग भुला ही दिया जाता है। क्षेत्रफल में लद्दाख सब से बड़ा संभाग (82,665 किलोमीटर) है, जबकि जनसंख्या सब से कम (147,104) है। तीनों संभागों में साम्प्रदायिक और सामाजिक भिन्नता है। कश्मीर मुस्लिम बहुल है, जम्मू हिन्दू बहुल और लद्दाख बौद्ध बहुल। तीनों संभागों में लद्दाख सब से दुर्गम और पिछड़ा है। इसी कारण इसकी अवहेलना भी की जाती रही है। प्रदेश के इतिहास में भी लद्दाख के योगदान की अनदेखी की गयी है। हालांकि, सामरिक दृष्टि से इसका योगदान बहुत बड़ा रहा है, विशेषकर कारगिल की लड़ाई के समय, क्योंकि चीन और पकिस्तान के साथ इसकी सीमायें सांझी हैं ।

अपनी नवीनतम पुस्तक "जम्मू-कश्मीर का विस्मृत अध्याय-कुशोक बकुला रिंपोछे" के माध्यम से डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने इस कमी को पूरा करने का एक सफल प्रयास किया है। उन्होंने इस पुस्तक में लद्दाख के कुशोक बकुला रिंपोछे के बारे पूरी जानकारी बड़ी बखूबी से प्रस्तुत की है। कुशोक बकुला कोई नाम नहीं है, बल्कि यह भी परम पावन दलाई लामा और पंचन लामा की तर्ज़ पर एक सांस्कृतिक व धार्मिक पद है जो पुनर्जन्म लेता है। कुशोक बकुला की विद्वत्ता की ऊंचाई को परम पावन दलाई लामा के सिवा और कोइ नहीं छू सकता। डॉ. अग्निहोत्री ने इसकी व्यावहारिकता व किंवदंतियों की विस्तृत चर्चा बड़े रोचक ढंग से की है।

जिन रिंपोछे का वर्णन पुस्तक में किया गया है वह 19वें कुशोक बकुला रिंपोछे हैं। वह बहु-आयामी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी शिक्षा-दीक्षा तिब्बत में हुई। बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने ज्योतिष, आयुर्वेद और एक्यूपन्क्चर का भी ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह वहां की जनता की सेवा करते रहे। क्षेत्र की पुरानी विकृतियों व बहुपति प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत काम किया। समाज को आधुनिक शिक्षा की ओर भी प्रेरित किया। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लद्दाख भारत का ही अंग बन कर रहेगा। शेख अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर लद्दाख के लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो वे अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार की धमकी शेख जम्मू के लोगों को पहले ही दे चुके थे।

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में तीन ही व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण रहे — एक शेख अब्दुल्ला, दूसरे पंडित प्रेमनाथ डोगरा और तीसरे कुशोक बकुला। जो महत्वपूर्ण काम शेख अब्दुल्ला की चालों को विफल कर जम्मू संभाग को भारत के साथ ही रहने देने के लिए प्रजा परिषद् के अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा ने किया, वही कार्य कुशोक बकुला रिंपोछे ने लद्दाख के लिए किया।

जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू लेह आये तो उन्होंने कुशोक बकुला रिंपोछे को राजनीति में आने का निमंत्रण दिया जिसे उन्होंने लद्दाख के हित में स्वीकार कर लिया- "मैं एक भिक्षु हूं और नियम के अनुसार तो मुझे राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन मैं शताब्दियों से चली आ रही इस परम्परा को तोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में लद्दाख का विकास बसा हुआ है"।

कुशोक बकुला रिंपोछे को प्रदेश संविधान सभा के लिए लद्दाख से चुना गया। शेख अब्दुल्ला के प्रधान मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कुशोक बकुला 1953 में लद्दाख मामलों के नए गठित मंत्रालय में उपमंत्री बने और बाद में 1967 तक राज्य मंत्री रहे। राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद रिंपोछे ने आम जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी। वह निर्भीक व्यक्ति थे। नेशनल कांफ्रेंस के सदस्य होने के बावजूद लद्दाख की अनदेखी पर संविधान सभा में खरी-खरी सुनाने से न चूके।

जब लद्दाख के लिए लोक सभा की एक अलग सीट बनी, तो 1967 में उस सीट के लिये कुशोक बकुला निर्विरोध चुने गए। रिंपोछे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना दिया। यह शेख अब्दुल्ला को गंवारा न बैठा। जब आयोग ने जम्मू-कश्मीर दौरे का प्रोग्राम बनाया तो शेख अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया कि इसके प्रदेश में आने से राज्य की स्वायत्तत्ता में दखलंदाज़ी होगी। शेख सरकार ने लद्दाख को साम्प्रदायिकता के आधार पर दो ज़िलों में बांट दिया — बौद्ध बहुल जिला लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल। शेख ने इस प्रकार दोनों समुदायों को आपस में भिड़ाकर कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहा था।

बाद में बकुला को केंद्र सरकार ने मंगोलिया में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया। भारत और मंगोलिया के संबंधों को मधुर बनाने में उनकी भूमिका अद्वितीय रही। मंगोलिया सरकार ने उन्हें सब से बड़े "पोलार स्टार" से सम्मानित किया। राजदूत के रूप में उन्होंने तिब्बत समस्या के हल करने के लिए कई प्रयास किये। वह ईसाई मिशनरियों द्वारा ग़रीब जनता को पैसे बांट कर धर्म परिवर्तन के सख्त खिलाफ थे। जब वह लन्दन गए तो ब्रिटेन की महारानी ने उन्हें बकिंघम महल में ठहराया। 4 नवम्बर 2003 को 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह त्याग दी।

पुस्तक अनेक ग्रंथों, पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं के अध्ययन से एक गहरे अनुसंधान का निचोड़ है। हर अध्याय के अंत में सन्दर्भों का ज़िक्र किया गया है जो पुस्तक की प्रमाणिकता को सजाते हैं। लद्दाख को न्याय मिला हो या न मिला हो, पर डॉ. अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र व जनता से अवश्य न्याय किया है। पुस्तक रोचक व पठनीय है। लेखक व प्रकाशक दोनों का ही प्रयास सराहनीय है। ■

सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का असंभव कार्य किया: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन ''मन की बात" में 28 अक्टूबर को कहा कि अगर आज हम एकीकृत भारत देख रहे हैं, तो इसका पूरा-पूरा श्रेय सरदार पटेल के रणनीतिक कौशल और उनकी बुद्धिमत्ता को जाता है।

श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए उनकी ईमानदारी और प्रतिबद्धता ऐसी थी कि किसान, मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, सब उन पर भरोसा करते थे। गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि राज्यों की समस्याएं इतनी विकट हैं कि केवल आप ही इनका हल निकाल सकते हैं और सरदार पटेल ने एक-एक कर समाधान निकाला और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने सभी रियासतों का भारत में विलय कराया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे जूनागढ़ हो या हैदराबाद, त्रावणकोर हो या फिर राजस्थान की रियासतें- वे सरदार पटेल ही थे जिनकी सूझबूझ और रणनीतिक कौशल से आज हम एक हिन्दुस्तान देख पा रहे हैं। एकता के बंधन में बंधे इस राष्ट्र को, हमारी भारत मां को देख करके हम स्वाभाविक रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल का पुण्य स्मरण करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज़ादी से लगभग साढ़े छह महीने पहले 27 जनवरी 1947 को विश्व की प्रसिद्ध इंटरनेशनल मैगज़ीन 'टाइम मैगज़ीन' ने जो संस्करण प्रकाशित किया था, उसके कवर पेज पर सरदार पटेल का फोटो लगा था। अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था और ये वैसा नक्शा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। ये एक ऐसे भारत का नक्शा था जो कई भागों में बंटा हुआ था। तब 550 से ज्यादा देशी रियासते थीं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत को लेकर अंग्रेजों की रुचि ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो इस देश को छिन्न-भिन्न करके छोड़ना चाहते थे। 'टाइम मैगज़ीन' ने लिखा था कि भारत पर विभाजन, हिंसा, खाद्यान्न संकट, महंगाई और सत्ता की राजनीति से जैसे खतरे मंडरा रहे थे। आगे 'टाइम मैगज़ीन' लिखता है कि इन सबके बीच देश को एकता के सूत्र में पिरोने और घावों को भरने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है सरदार वल्लभभाई पटेल।

गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दो गुनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुम्बी प्रतिमा है। हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पायेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की धरती पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'टाइम मैगज़ीन' की स्टोरी लौह पुरुष के जीवन के दूसरे पहलुओं को भी उजागर करती है। कैसे उन्होंने 1920 के दशक में अहमदाबाद में आयी बाढ़ को लेकर राहत कार्यों का प्रबंधन

किया। कैसे उन्होंने बारडोली सत्याग्रह को दिशा दी।

उन्होंने कहा कि इस साल 31 अक्टूबर बहुत ही खास होगा, क्योंकि सरदार पटेल को ''सच्ची श्रद्धांजलि" के तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित इस प्रतिमा की ऊंचाई अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दो गुनी है। ये विश्व की सबसे ऊंची गगनचुम्बी प्रतिमा है। हर भारतीय इस बात पर अब गर्व कर पायेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत की धरती पर है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वो सरदार पटेल जो जमीन से जुड़े थे, अब आसमान शोभा बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि देश का हर नागरिक 'मां-भारती' की इस महान उपलब्धि को लेकर के विश्व के सामने गर्व के साथ सीना तान करके, सर ऊंचा करके इसका गौरवगान करेगा और स्वाभाविक है हर हिन्दुस्तानी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का मन करेगा और मुझे विश्वास है हिन्दुस्तान से हर कोने से लोग अब इसको भी अपना एक बहुत ही प्रिय स्थान के रूप में पसंद करेंगे।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। इंदिरा जी को भी हमारी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

जापान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे

टोक्यो (जापान) में भारतीय समुदाय की बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जापान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भारतीय समुदाय के लोग

नई दिल्ली में भारत–इटली तकनीक सम्मेलन में इटली के प्रधानमंत्री श्री जिएसेपे कॉन्टे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करते यूनाइटेड स्टेट्स–इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सदस्यगण

आईएनएस अरिहन्त के अपने पहले डेटरेंस पेट्रोल से लौटने के बाद इसके कर्मियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20